RNI No. : TNHIN/2013/52520 ■ वर्ष - 14 ■ अंक - 9 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- चेन्नई » शुक्रवार » 31-07-2026 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

4 राजस्थान में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी : गहलोत

6 बदलता परिदृश्य और आरक्षण की प्रासंगिकता

7 अच्छे किरदार मिलना मेरी किस्मत का हिस्सा है : शहनाज गिल

फर्स्ट टेक

भारत-म्यांमार सीमा पर छह साल बाद फिर शुरू हुआ पैंगसौ पास 'बॉर्डर हाट'

ईटानगर/भाषा। अरुणाचल प्रदेश के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री न्यातो दुकम ने बृहस्पतिवार को चांगलांग जिले में भारत-म्यांमा सीमा पर स्थित पैंगसौ पास 'बॉर्डर हाट' (सीमावर्ती बाजार) का फिर से संचालन शुरू होने पर इसका उद्घाटन किया। नामपोंग स्थित पैंगसौ पास पर यह सीमावर्ती बाज़ार छह साल के अंतराल के बाद दोबारा शुरू हुआ है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सभा को संबोधित करते हुए दुकम ने स्थानीय आर्थिक विकास को गति देने में व्यापारिक गतिविधियों की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों और प्रशासनिक निकायों सहित सभी हितधारकों से इस सीमा पार व्यापार को एक जीवंत और टिकाऊ आर्थिक ज़रिया बनाने में सक्रिय रूप से जुटने का आग्रह किया।

चीन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चिनफिंग की भागीदारी पर स्थिति साफ नहीं की

बीजिंग/भाषा। चीन ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह भारत में सितंबर में प्रस्तावित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के नई दिल्ली के प्रयासों का समर्थन करता है। हालांकि, उसने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने से जुड़े सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बीजिंग में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा, ब्रिक्स उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा, चीन ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को बहुत महत्व देता है और इसमें सक्रिय रूप से योगदान देता है।

लाहौर में तीन मंजिला मकान ढहा, एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत

लाहौर/भाषा। पाकिस्तान के लाहौर शहर में जन्मदिन के जश्न के दौरान तीन मंजिला मकान ढहने से एक ही परिवार के कम से कम 11 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि मरने वालों में तीन बच्चे भी शामिल हैं। लाहौर के घनी आबादी वाले निचले इलाके हरबंसपुरा में बुधवार देर रात जब यह हादसा हुआ, तब मकान में जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था। माना जा रहा है कि हाल ही में हुई भारी मानसूनी बारिश के कारण यह इमारत कमजोर हो गई थी। एजाज ने बताया, जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भाइयों की बहन और उसके बच्चे भी आए हुए थे। इसी दौरान अचानक मकान ढह गया, जिससे लगभग 20 लोग मलबे के नीचे दब गए।

31-07-2026 सूर्यास्त 6:36 बजे | 01-08-2026 सूर्योदय 5:56 बजे

BSE 77,928.15 (+273.55) | NSE 24,317.15 (+66.96)

सोना 14,866 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम | चांदी 235,000 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

गड्ढे में शहर

घायल है जनता सारी ही,
किसको कोसे किस पर भड़कें।
बहरे से हैं जनप्रतिनिधि भी,
केवल चुनाव में ही कड़कें।
चालान बड़ा लेने को बस,
ट्रेफिक वालों के मन फड़कें।
चालक क्या देखे गड्ढों को,
है गड्ढों में सारी सड़कें।।

वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिला

विवादित इतिहास पर बहस फिर शुरू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। संसद ने 'राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' को बृहस्पतिवार को पारित कर दिया, जिसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम' के गायन के दौरान किसी भी तरह के व्यवधान या उसके अपमान को आपराधिक कृत्य मानते हुए तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ एक सदी से अधिक समय से देशभक्ति की भावना को जागृत करने और सियासी विवादों को हवा देने वाले राष्ट्रगीत के इतिहास को लेकर लंबे समय से जारी बहस फिर शुरू हो गई है। सरकार ने कहा कि यह विधेयक 'वंदे मातरम' को कानून के तहत राष्ट्रगान 'जन गण मन' के बराबर का दर्जा देता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रगान गाने से जानबूझकर रोकने या किसी सभा में इसके गायन में व्यवधान पैदा करने पर लगने वाले दंडात्मक प्रावधानों को राष्ट्रीय गीत पर भी लागू किया गया है। ऐसे अपराधों के लिए तीन साल तक के कारावास या जुर्माने या दोनों सजा का प्रावधान है।

'राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' को लोकसभा ने द्रमुक समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने 76 साल के शासनकाल में 'वंदे मातरम' को उचित सम्मान देना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसने तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा लिया। इससे पहले, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सांसद के कनिमोई ने विधेयक के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि सरकार इसके जरिये हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रीयता के रूप में पेश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 76 साल के शासनकाल में 'वंदे मातरम' को वह सम्मान नहीं दिया, जिसका राष्ट्रगीत के तौर पर वह हकदार था। राष्ट्रगीत को लेकर समय-समय पर तीखी बहस होती रही है-खासकर इसके धर्मनिरपेक्ष या इस्लाम-विरोधी स्वरूप और आजादी की लड़ाई में इसकी भूमिका को लेकर।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि 1937 में राष्ट्रगीत के अहम हिस्सों को हटा दिया गया था, जिससे बंटवारे की नींव पड़ी। उन्होंने कहा था कि ऐसी विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए एक चुनौती है। बंगाली उपन्यासकार-कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में 'वंदे मातरम' की रचना की थी, जिसमें मातृभूमि को देवी काली के रूप में दर्शाया गया है। यह रचना तब से ही कई बार राजनीतिक विवादों के केंद्र में रही है।

'वंदे मातरम' को सबसे पहले 1882 में साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन' में चटर्जी के उपन्यास 'आनंदमठ' के हिस्से के तौर पर प्रकाशित किया गया था। सदी के आखिर तक यह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का नारा बन गया, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेताओं ने लोकप्रिय बनाया।

संसद ने दी प्रश्नपत्र लीक निरोधक विधेयक को मंजूरी, विपक्ष का वाक आउट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा ने बृहस्पतिवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' को मंजूरी दे दी और इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गयी जिसमें प्रश्न पत्र लीक करने के अपराध में दस साल तक की सजा तथा 50 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। नीट प्रश्नपत्र लीक की पृष्ठभूमि में लाए गए लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 को लोकसभा ने एक दिन पहले ही मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। सदन ने विपक्ष द्वारा विधेयक पर लाये गये संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। मंत्री के जवाब के पहले कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से वाक आउट किया।

वाक आउट पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष पूरी तरह से मुद्दाविहीन हो गया है और उसने अपनी करतूत से इसे साबित भी कर दिया है। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा

कि यह विधेयक सिर्फ पेपर लीक से नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि परीक्षा में कदाचार से जुड़े विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एनटीए ही नहीं, बल्कि यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उन्होंने छात्रों से जुड़े विषयों का जिक्र करते हुए कहा कि यह ऐसा मुद्दा है जो हर भारतीय नागरिक को प्रभावित करता है, यह विषय देश के हर परिवार, हर अभिभावक से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिस विकसित भारत 2047'' का जिक्र करते हैं, उसके लिए ये युवा और छात्र बहुत बड़े निवेश हैं।

उन्होंने चर्चा में विभिन्न विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए आंकड़ों की सत्यता को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि चर्चा में जिक्र किया गया कि प्रश्नपत्र लीक के 152 मामले सामने आए हैं। उन्होंने सवाल किया कि ये आंकड़े कहां से मिले, यह बताना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चर्चा में कहा गया कि भारत में प्रभावित बच्चों की संख्या करोड़ों में बतायी गयी जो अवास्तविक है। सिंह ने शिक्षा में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लायी गयी नई शिक्षा नीति से स्थिति में व्यापक बदलाव आया और बच्चों को अपना पसंदीदा विषय चुनने की व्यापक आजादी मिली। उन्होंने कहा कि पहले छात्रों को विषयों के चुनाव में सीमित विकल्प मिलते थे और स्थिति में बदलाव बहुत पहले किया जाना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि सरकार ने मेडिकल शिक्षा को वहनीय बनाने पर जोर दिया और मैनेजमेंट कोटा'' व्यवस्था को खत्म किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सीटों में वृद्धि करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने न सिर्फ मेडिकल शिक्षा में बल्कि उच्च शिक्षा पर जोर दिया है और विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने लंबित रिक्तियों और प्रोन्नति का भी जिक्र किया और कहा कि बड़े पैमाने पर कर्मियों को प्रोन्नति दी गयी। लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम पांच साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम सात साल के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है।

कांग्रेस हिंदू धर्म के बारे में नकारात्मकता फैलाना चाहती है : सुधांशु त्रिवेदी

नई दिल्ली/भाषा। भाजपा ने आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटि के खिलाफ प्रियंका गांधी के गोमूत्र विशेषज्ञ'' वाले बयान को लेकर बृहस्पतिवार को कांग्रेस की तीखी आलोचना की और आरोप लगाया कि मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के बारे में नकारात्मकता फैलाना चाहती है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि ''यह दिखाता है कि कांग्रेस भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के बारे में कितनी नकात्मकता फैलाना चाहती है।'' त्रिवेदी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ''...उनकी वजह से हमने अपने ज्ञान के कई स्रोत खो दिए, क्योंकि वे नेहरू के जमाने से ही पश्चिम के अंधभक्त बने रहे।'' उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पता होना चाहिए कि अमेरिका में गोमूत्र के लिए एक पेटेंट है, जो इसके ''एंटी-बैक्टीरियल'' और ''एंटी-फंगल'' औषधीय गुणों को स्वीकार करता है।

मदद

असम के नगांव जिले में बृहस्पतिवार को राज्य भर के बाढ़ पीड़ितों की मदद और पुनर्वास प्रयासों के समर्थन में राहत कोष जुटाने के अभियान में हिस्सा लेती एक असमिया गायिका।

आईएएसवी त्रिवेणी से दुनिया का चक्कर लगाने वाली महिला अधिकारियों ने रूढ़ीवादी सोच तोड़ी : राजनाथ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को भारतीय सशस्त्र बलों की उन नौ महिला अधिकारियों को सम्मानित किया, जिन्होंने हाल में समुद्री प्रदक्षिणा' अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि ने उन रूढ़ीवादी धारणाओं को तोड़ दिया कि महिलाएं मुश्किल सैन्य अभियानों को पूरा नहीं कर सकतीं। 'समुद्री प्रदक्षिणा' अभियान के तहत थलसेना, नौसेना और वायुसेना की नौ महिला अधिकारियों ने भारतीय सेना नौकायन पोत (आईएएसवी) त्रिवेणी पर सवार

होकर पहली बार दुनिया का चक्कर लगाने का कारनामा कर दिखाया। राजनाथ ने महिला अधिकारियों से कहा, आपने साबित कर दिया कि शारीरिक क्षमता, मानसिक मजबूती और नेतृत्व क्षमता किसी लिंग तक सीमित नहीं हैं। भारत की हर बेटी आपको देखकर खुद में यह भरोसा जगा सकती है कि वह भी समुद्र पार कर सकती है और दुनिया जीत सकती है। उन्होंने चार महासागरों में करीब 25,500 समुद्री मील की दूरी तय करते हुए 314 दिन में समुद्री प्रदक्षिणा' अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली टीम के साहस और दृढ़ संकल्प की सराहना की।

राजनाथ ने इस अभियान को नारी शक्ति' का प्रमाण करार देते हुए कहा कि यह तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल और सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो हर भारतीय को प्रेरित करेगा।

उन्होंने महिला अधिकारियों की काबिलियत और आत्मविश्वास को अविश्वसनीय बताते हुए कहा कि 'समुद्र प्रदक्षिणा' अभियान की सफलता ने उन रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ दिया है कि महिलाएं मुश्किल सैन्य अभियान पूरे नहीं कर सकतीं। राजनाथ ने कहा कि भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना की महिला अधिकारियों ने साझा लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक ही जहाज पर, एक ही ध्वज के तले साथ मिलकर यात्रा की।

'हसीना को स्वदेश लौटने पर आत्मसमर्पण करने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा'

ढाका/भाषा। बांग्लादेश के कानून मंत्री एम. असदुज्जमां ने बृहस्पतिवार को कहा कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से लौटने पर तुरंत गिरफ्तार किए जाने की संभावना है और उन्हें सीधे अदालत में पहुंचकर आत्मसमर्पण करने का मौका नहीं मिलेगा। यह बयान हसीना के एक समाचार एजेंसी को दिए उस साक्षात्कार के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी जान को खतरा होने के बावजूद वह दिसंबर तक अपने देश लौटने के लिए दृढ़ हैं। खबरों के मुताबिक, उन्होंने कहा, हो सकता है कि मेरी हत्या कर दी जाए। हो सकता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। हो सकता है कि मुझे जेल भेज दिया जाए... मुझे अपनी किस्मत के बारे में पूरी जानकारी है। फिर भी, मैं वापस जाना चाहती हूं, क्योंकि मेरे लोग मुझे बुला रहे हैं।''

इस महीने की शुरुआत में उनके कुछ और साक्षात्कार सामने आए थे, जिनसे पता चला था कि वह अपनी पार्टी के सहयोगियों के साथ इस साल के आखिर तक बांग्लादेश लौटने की संभावना पर चर्चा कर रही हैं। असदुज्जमां ने कहा कि 78-वर्षीय हसीना को लौटने का अधिकार है, लेकिन कानून अपना काम करेगा और हम कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ भी नहीं करेंगे। मंत्री ने पत्रकारों से कहा, मौत की सजा सुनाए जाने के बावजूद, बांग्लादेशी नागरिक होने के नाते अगर वह घर लौटकर कानून का सम्मान करते हुए आत्मसमर्पण करना चाहती हैं, तो हो सकता है कि ऐसा करने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। हम उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जो कानून ने हमें दिया है। जब उनसे पूछा गया कि अंतरिम सरकार द्वारा उनका पासपोर्ट रद्द किए जाने के बाद वह कैसे लौट सकती हैं, तो मंत्री असदुज्जमां ने कहा, यह उनकी समस्या है, मेरी नहीं।

टीवीके ने कावेरी मामले में द्रमुक पर साधा निशाना, कहा- तमिलनाडु के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाएगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। सत्ताधारी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) ने बृहस्पतिवार को मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना के मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार की आलोचना करने के लिए द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) पर पलटवार किया और कहा कि वह राज्य के अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेगी। विपक्षी द्रमुक ने कहा कि टीवीके इस तरह बात कर रही है जैसे कि पड़ोसी राज्य कर्नाटक की प्रस्तावित जलाशय परियोजना को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब उसके संस्थापक सी. जोसेफ विजय ने 10 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। टीवीके ने एक बयान में पूछा, अगर ऐसा है तो क्या द्रमुक अप्रत्यक्ष रूप से यह मान रही है कि राज्य में अपने पांच साल के शासन के दौरान वह सोती' रही?'' पार्टी ने पिछली द्रमुक सरकार पर तमिलनाडु के हितों की रक्षा करने में 'विफल' रहने का आरोप लगाया। बयान में कहा गया है कि चुनावी हार के बावजूद द्रमुक नेता इस तरह बात कर रहे जैसे कि वे अब भी सत्ता में हैं। इसमें कहा गया, इससे पता चलता है कि द्रमुक असलियत से कितनी दूर है। अगर उसने सत्ता में रहते हुए कदम उठाए होते, तो लोग उसे विपक्ष में नहीं भेजते। अपनी विफलताओं को स्वीकार करने के बजाय, द्रमुक निराशा, ईर्ष्या और सत्ता पाने की बेताबी से प्रेरित राजनीति में लगी हुई है।'' द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने कहा कि टीवीके सरकार ने कई मामलों में किसानों को निराश किया है। इनमें फसल ऋण माफी, प्रस्तावित मेकेदातु संतुलित बांध के मुद्दे को संभालने का तरीका, मेट्टूर बांध खोलने में देरी जिससे कुरुवई धान की खेती पर असर पड़ा, और मेकेदातु विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुलाने में देरी शामिल है। उन्होंने घोषणा की कि द्रमुक तीन अगस्त को तंजावुर में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन के नेतृत्व में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। वे मांग करेंगे कि सरकार कावेरी के पानी पर तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए और कावेरी डेल्टा के किसानों के लिए एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा करे। पूर्व मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि किसानों की चिंताओं को नजरअंदाज करने से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को वरिष्ठ मंत्रियों के एक समूह के साथ वैश्विक स्तर के सुरक्षा हालात तथा होर्मुज जलडमरूमध्य, काला सागर, लाल सागर और अदन की खाड़ी सहित विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष की स्थिति के बावजूद आपूर्ति श्रृंखला को निर्बाध बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) की बैठक में समिति के स्थायी सदस्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार, बैठक में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों, उनके सुरक्षा संबंधी प्रभावों तथा भारत के आयात और आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ रहे असर की व्यापक समीक्षा की गई।

गुरु पूनम मेले में दिखा गुरु भक्ति का माहौल

अरसीकेरे/दक्षिण भारत। शहर के दक्षिण नाकोड़ा तीर्थ एवं जाजूर स्थित दक्षिण शांतिसूरी तीर्थ में बुधवार को गुरु पूनम मेले का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में गुरु भक्त शामिल हुए।

खींचा परिवार बसों द्वारा संघ यात्रा लेकर तीर्थ पहुंचकर गुरुदेव एवं भैरवदेव की विशेष पूजा कर गुरु वंदना समारोह में शामिल हुआ। तीर्थ पर पार्श्व भैरव महापूजन एवं अष्ट प्रकारी पूजन के पश्चात भैरवदेव को छप्पनभोग, 108 श्रीफल, पुष्प अर्पण एवं तेल चढाया गया। बेंगलूरु भैरव भक्त परिवार व गुरु समर्पण समिति के सदस्यों ने शाम को आयोजित भक्ति कार्यक्रम में श्रद्धा से भाग लिया और स्थानीय गायकों ने भजनों की प्रस्तुति दी।

सम्मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

काँठा प्रान्त जैन संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर स्थानकवासी जैन समाज, हुब्बल्ली के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंघी के निर्विरोध मनोनीत होने पर हुब्बल्ली के वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के सदस्यों ने उनसे मुलाकात कर सम्मानित किया। इस मौके पर हुब्बल्ली संघ के अध्यक्ष बाबूलाल पारेख, कार्याध्यक्ष गौतम भुरट, उपाध्यक्ष शांतिलाल खिवेंसरा, मंत्री प्रकाश कटारिया, कोषाध्यक्ष कांतिलाल बोहरा सहित अन्य सदस्य व समाज बंधु उपस्थित थे।

दक्षिण पश्चिम रेलवे

ई-प्रोक्यूअरमेंट (आईआरईपीएस)

निविदा सूचना सं: HE-06-2026-27

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदाएं (आईआरईपीएस) आमंत्रित करते हैं:

ई.सं	कार्य का नाम	अनुमानित लागत
1	**उप कार्य-1:**	रु. 65,79,301.42

तोरणगल्लू में रनिंग रूम को बढ़ाने (80 बेड) के लिए इलेक्ट्रिकल व्यवस्था। **उप कार्य-2:** तोरणगल्लू में नए क्रू बुकिंग लॉबी के प्रस्तावित निर्माण के लिए इलेक्ट्रिकल व्यवस्था।

2	**इलेक्ट्रिकल**	रु. 17,42,933.81

व्यवस्था: हुबली रेल सौधा में कार्मिक विभाग के स्टाफ हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, अधिकारियों के चैंबर और वॉशरूम में सुधार कार्य।

3	**हाई मास्ट की**	रु. 93,62,131.05

व्यवस्था: हुबली साउथ (एसयूबीएल) - 04, कुडगी (केडीजीआई) - 02, तोरणगल्लू (टीएनजीएल) - 02, बिंकाडाकट्टी (बीकेआईटी) - 02, होमबल (एचबीएल) (बीटी साइडिंग) - 02 और निदावंडा (एनवीडी) में 02। (कुल: 14)।

निविदाओं जमा करने की अंतिम तिथि: 22.08.2026, 11:00 बजे तक

विवरण के लिए लॉग ऑन करें www.ireps.gov.in में

वरिष्ठ विभागीय विद्युत इंजीनियर/सामान्य हुबली

PUB/339/AAMG/PRB/SWR/2026-27

आसान टिकट बुकिंग, PNR स्थिति और दूसरी रेलवे सेवाओं के लिए **RailOne** ऐप डाउनलोड करें।

South Western Railway - SWR | SWRRLY | SWRAILWAYHQ | sw_railways

महेन्द्र मुणोत ने किए साध्वी दर्शन, लिया आशीर्वाद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के विजयनगर स्थित मारुति मेडिकल के प्रमुख व गौभक्त महेन्द्र मुणोत ने विजयनगर स्थानक भवन में चातुर्मास हेतु विराजित साध्वी डॉ सुमंगलप्रभाजी के दर्शन किए व आशीर्वाद प्राप्त किया। साध्वीश्री ने मुणोत के गौ सेवा एवं शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की तथा आशीर्वाद दिया। मुणोत ने कहा कि जैन कुल में पैदा होना मेरे लिए सौभाग्यवती बात है। अहिंसा एवं सेवा के संस्कार मुझे बचपन में विरासत में प्राप्त हुए। महान जैन संत मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब मेरे आदर्श हैं और उनके सिद्धांत कम खाना, गम खाना और नम जाना को मैंने अपने जीवन में अपनाया जिससे मेरा जीवन ही बदल गया। जैन धर्म जाति या संप्रदाय का नाम नहीं, चरित्र एवं संस्कारों का नाम है।

श्रावणमास में 9 फीट ऊंचे विशेष शिवलिंग के समक्ष हुए अनेक धार्मिक अनुष्ठान

भूमिदानदाता परिवार व सहयोगियों का हुआ सम्मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। पंडित राजेंद्र कुमार शर्मा एवं ओमप्रकाश शर्मा के सान्निध्य में मागड़ी रोड के किंतनहल्ली स्थित लक्ष्मी ओरा फार्म हॉउस में सावन के पवित्र मास के प्रथम दिवस गुरुवार को 12.50 लाख रुद्राक्षों से बने 9 फीट ऊंचे शिवलिंग की विशेष पूजा की गई तथा निर्माण होने वाले मंदिर में प्रतिष्ठित होने वाले शिवलिंग पर रुद्राभिषेक-जलाभिषेक किया गया। काशी से आए विद्वान पंडितों द्वारा विभिन्न शिवभक्तों ने शिवलिंग पर अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए। भजन गायकों ने बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए श्रावण विशेष भजनों की प्रस्तुति दी जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने श्रद्धा से साथ दिया।

बेंगलूरु में पहली बार इस तरह लाखों रुद्राक्षों से शिवलिंग का निर्माण किया गया है जो कि मुख्य आकर्षण का केन्द्र है। इस विशेष शिवलिंग के दर्शनार्थ बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

कार्यक्रम के अंत में पंडित राजेन्द्रकुमार शर्मा द्वारा मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान करने वाले लक्ष्मी चैन्स प्रतिष्ठान के सुरेशकुमार, सावनकुमार, गौतमकुमार व महावीरकुमार मेहता परिवार सहित अन्य सहयोग देने वालों का सम्मान किया गया। महाआरती के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। शाम को भजनों का आयोजन किया गया।

जो स्वयं को जीतकर लोककल्याण में समर्पित हो, वही सच्चा शासक : मुनिश्री वीरसागर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

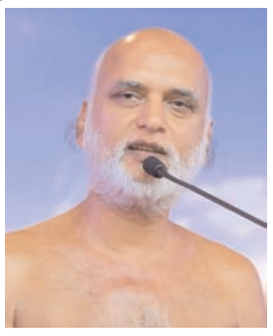

बेंगलूरु। वीर शासन जयंती के अवसर पर ज्ञानोदय परिसर तुबरहल्ली में विराजित मुनिश्री वीरसागरजी ने श्रद्धालुओं को भगवान महावीर के शासन के वास्तविक स्वरूप का गहन संदेश दिया। अपने प्रवचन में मुनिश्री ने कहा कि भगवान महावीर का शासन किसी भय, हिंसा, शक्ति या अधिकार पर आधारित नहीं था, बल्कि आत्मविजय, अहिंसा, निस्वार्थ सेवा और लोककल्याण पर आधारित था। उन्होंने कहा कि संसार के सामान्य शासक दूसरों पर अधिकार स्थापित करके शासन करते हैं, जबकि भगवान महावीर ने स्वयं के भीतर के अहंकार, लोभ और भय पर विजय प्राप्त कर समस्त जीवों के हृदय पर राज्य किया। यही कारण है कि ढाई हजार वर्षों के बाद भी उनका शासन मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है।

मुनिश्री ने स्पष्ट किया कि वास्तविक नेतृत्व वह नहीं है जो लोगों से भय या दबाव के माध्यम से अपनी बात मनवाए, बल्कि वह है जिसे लोग स्वेच्छा से स्वीकार करें। परिवार, समाज, संस्था अथवा राष्ट्र-हर स्तर पर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को अपने आचरण, सेवा, त्याग और करुणा से लोगों का विश्वास अर्जित करना चाहिए। मुनिश्री ने कहा कि केवल आत्मकल्याण ही पर्याप्त नहीं है। तीर्थंकर भगवान सम्पूर्ण मानवता के लिए धर्म, देव, गुरु और शास्त्र की ऐसी परंपरा स्थापित करते हैं, जिससे अनंत जीवों का कल्याण होता है।

भगवान महावीर की दिव्यध्वनि और उनके द्वारा स्थापित जिनशासन के कारण आज भी मोक्षमार्ग संसार के लिए सुलभ है। यदि प्रत्येक व्यक्ति आत्मसंयम, अहिंसा, निस्वार्थ सेवा और परोपकार को अपने जीवन का आधार बनाए, तभी इस पर्व का वास्तविक उद्देश्य सार्थक होगा।

सीडब्ल्यूएमए ने तमिलनाडु के लिए कावेरी का 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने की सिफारिश को बरकरार रखा:रेड्डी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसके तहत अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक कावेरी का पानी छोड़ा जाना है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार दो अगस्त को मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी। 'पीटीआई-भाषा' से बात करते हुए रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर चर्चा करने और सीडब्ल्यूएमए के फैसले पर राज्य की प्रतिक्रिया तय करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

मंत्री ने कहा, सीडब्ल्यूएमए ने सीडब्ल्यूआरसी के आदेश को बरकरार रखा है। अगले कदम के बारे में पूछे जाने पर रेड्डी ने कहा, मुख्यमंत्री ने दो अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हम उसमें तय करेंगे कि आगे क्या करना है। इस आदेश के बाद कर्नाटक में नाराजगी है क्योंकि राज्य गंभीर सूखे का सामना कर रहा है।

मानव जन्म से नहीं, कर्म से बनता है महान : राष्ट्रसंत कमलमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मैसूरु। शहर के स्थानकवासी जैन संघ हल्लदकेरी के तत्वावधान में स्थानक भवन में विराजित राष्ट्रसंत कमलमुनिजी कमलेश ने कहा कि संपूर्ण मानव समाज के शरीर की रचना एक समान है। सबके खून का रंग लाल है। जन्म के समय किसी के सिर पर जाति अथवा धर्म नहीं लिखा हुआ होता है। किसी कुल में जन्म लेने मात्र से कोई ऊंचा अथवा नीचा नहीं हो जाता है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर नीच काम करें वह नीच है। सामान्य कुल में जन्म लेकर महान काम करें तो विश्व पूजनीय बन सकता है। जन्म से किसी को ऊंचा और नीचा मानना साक्षात परमात्मा का अपमान करने के समान गौर अज्ञानता का परिचायक है। यदि भगवान को भेद मंजूर होता तो ऊंचे कुल वाले का खून लाल और नीचे कुल वाले का खून हरा कर देते।

मुनिश्री ने विकृत वर्ण व्यवस्था पर करारी चोट करते हुए कहा कि सभी आत्माएं परमात्मा के समान हैं। जाति के आधार पर अपमानित अथवा सम्मानित करना सरासर अन्याय है। चारों ही वर्ण हमारे अंदर विद्यमान हैं।

जब हम साधना करते हैं तो पंडित हैं, व्यापार करते हैं तो वणिक है और अपनी सफाई करते हैं तब शूद्र है, जब आपकी रक्षा के लिए आगे आते हैं, तब हम क्षत्रिय हैं। फिर किस आधार पर भेदभाव का व्यवहार किया जाता है? भेदभाव का व्यवहार संपूर्ण मानवता पर कलंक है।

गोवा तमनार ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय आरएमजेड इन्फिनिटी, पाँचवा तल, प्लॉट नं.-15, उद्योग विहार, फेस IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम - 122015, हरियाणा, भारत | CIN : U40106HR2017PLC113920 | फोन नं.: 0124-4562000

सार्वजनिक सूचना

गोवा तमनार ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड (जीटीटीपीएल) जिसका पंजीकृत कार्यालय आरएमजेड इन्फिनिटी, पाँचवा तल, प्लॉट नं. -15, उद्योग विहार, फेस IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम - 122015, हरियाणा, भारत में है, भारत सरकार से उसे विद्युत पारेषण के लिए विद्युत लाइनें बिछाने या विद्युत संयंत्र लगाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत, या कार्यों के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्देश्य से, जो टेलीग्राफ प्राधिकरण भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत सरकार द्वारा स्थापित किए गए या अनुरक्षित किए गए या इस प्रकार स्थापित किए जाने वाले या अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्य से टेलीग्राफ लाइनें बिछाने और खंभे लगाने के संबंध में है, सभी शक्तियाँ प्रदान करने के लिए आवेदन करना चाहता है और वह निम्नलिखित पारेषण योजनाओं के लिए सर्वेक्षण, निर्माण, संस्थापन, निरीक्षण, स्थापन और अन्य कार्य करने के उपरांत कमीशनिंग, परिचालन, रखरखाव और अन्य कार्यों को हाथ में लेगा।

पारेषण योजना का नाम: ''गोवा तक अतिरिक्त 400 केवी फीड और रायगढ़ (तमनार) पूल में पूल की गई निर्माण परियोजनाओं से बिजली की निकासी के लिए अतिरिक्त प्रणाली''।

योजना के अंतर्गत शामिल कार्य:

ए. गोवा तक अतिरिक्त 400 केवी फीड

(i) नरेंद्र (मौजूदा) के एक सर्किट का एलआईएलओ - Xeldem में नरेंद्र (नया) 400 केवी डी/सी क्वाड लाइन
(ii) Xeldem-म्हापसा 400 केवी डी/सी (क्वाड) लाइन
(iii) Xeldem-Xeldem (मौजूदा) 220 केवी एचटीएलएस डी/सी लाइन (ट्विन मूस कंडक्टर के लिए एम्पैसिटी)
(iv) Xeldem में 400/220 केवी सबस्टेशन की स्थापना

बी. रायगढ़ (तमनार) पूल में विद्युतजनन परियोजनाओं से बिजली की निकासी के लिए अतिरिक्त प्रणाली :

(i) धरमजयगढ़ पूल सेक्शन बी - रायगढ़ (तमनार) पूल 765 केवी डी/सी लाइन

उपरोक्त पारेषण परियोजना को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत सीईए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या 26/3/PSPA-I/2017/491-492 दिनांकित 15.06.2017 के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई है।

जीटीटीपीएल को एमओपी द्वारा दिनांक 28.11.2018 के अपने राजपत्र आदेश के माध्यम से धारा 164 की स्वीकृति पहले ही प्रदान की जा चुकी है। यह परियोजना आज की तिथि में एक एलिमेंट को छोड़कर कार्यान्वित हो चुकी है, अर्थात Xeldem में नरेंद्र (मौजूदा) - नरेंद्र (नया) 400 केवी डी/सी क्वाड लाइन के एक सर्किट का एलआईएलओ। उक्त लाइन के मार्ग को माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 07.04.2022 के निर्देशों के अनुसार पुनः संरेखित किया गया है।

नरेंद्र (मौजूदा) के एक सर्किट का एलआईएलओ - Xeldem में नरेंद्र (नया) 400 केवी डी/सी क्वाड लाइन इस योजना के अंतर्गत आने वाली पारेषण लाइनें निम्नलिखित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उनके ऊपर से, उनके चारों ओर से और उनके बीच से गुजरेंगी।

क्र.	गाँवों के नाम	तहसील	जिला	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	धारबंदोर, दरबंदोर, दरबंदर, मोल्लेम	धारबंदोर	दक्षिण गोवा	गोवा
2.	अंबेटिमेडे, अखेती, कुनगिनी, कुनगिन, इवली घोटगे, इवली, इलियाधाबे, इलियादावे, दुर्गा, दुर्ग, कामारे, काम्र, कामारा, कम्रे, कसर्ले, कसरले, बोरेगली, बोरीगली, असु, चपेली, चपोली, चपाली, रामानगर, रामनगर, रामानगरा (शीतवाड), रामनगरदाली, रामनगरक्रली, इल्वा, नववाड, जलकनहट्टी, घोलशेट, गोलटेवाडी, कोलेवाडी, फतरबदुद्दी, अदली, सीतावाडी, अस्टोली, धर्मशाला, कुरहाडवाडी, चंदवाडी, चंदेवाडी, म्हतरवाड़ा, कोनशेट, अट्ली डोंगर, कुंगिन, अंबेली इलावा	जोइडा (सुपा)	उत्तर कन्नड़	कर्नाटक
3.	मुंडवाडा पिंपले, मुंडवाड-पिंपले, मुंडवाडा-पिंपला, मंजपेलोंडा, मंजरपाई के जी, मंजरपाल, पिंपल, शिंधोली खुर्द, सकनाली, शिंधोली बुदरूक, भाटेरवाड़ा, शिंदोली बीके, भाटेरवाडी, सोनेनहट्टी (भुरानकी, भुरंकी), शिंदोली केएच, मंजरपाई के जी, मलवाड़	खानापुर	बेलगावी	कर्नाटक
4.	देवगांव, देवागांव	कित्तूर	बेलगावी	कर्नाटक
5.	गुलदकोप्प, गुल्लदकोप्प, मडिकोप्प, दुर्गदकेरी, मटिकोप्प, मडिकोप्प, नरेंद्र	धारवाड़	धारवाड़	कर्नाटक

अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मार्ग संरेखण की प्रति उपलब्ध है। एतद द्वारा आम जनता को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से दो महीने के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में लिखित रूप से ट्रान्समिशन लाइन के प्रस्तावित मार्ग पर टिप्पणी/अभ्यावेदन करने का नोटिस दिया जाता है। अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संपर्क करें :

नाम: टी. अमरेंद्रनाथ रेड्डी **। पदनाम:** डायरेक्टर

कार्यालय का पता: आरएमजेड इन्फिनिटी, पाँचवा तल, प्लॉट नं.-15, उद्योग विहार फेस IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम-122015, हरियाणा, भारत.

ईमेल पता: tan.reddy@resonia.com / sangeet.attri@resonia.com **। फोन नं.:** 8745915399

तेरापंथ ट्रस्ट गांधीनगर के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण संपन्न

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। तेरापंथ ट्रस्ट, गांधीनगर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह साध्वी पावनप्रभाजी के सान्निध्य में सम्पन्न हुआ। ट्रस्ट के निवर्तमान अध्यक्ष सुशीलकुमार चोरड़िया ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष माणकचंद बलदोटा को अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। बलदोटा ने पवनकुमार चोपड़ा एवं रमेशचंद दक को उपाध्यक्ष, कन्हैयालाल चिप्पड़ को मंत्री, सुनीलकुमार बैद को सहमंत्री, माणकचंद संचेती को कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों को अपने पद के दायित्वों की शपथ दिलाई। बलदोटा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पद उनके लिए सम्मान के साथ-साथ सेवा का उत्तरदायित्व भी है।

साध्वी पावनप्रभाजी ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता स्वयं को सेवा भाव से जोड़कर कार्य करे तो संगठन निरंतर प्रगति करता है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से कहा कि वे परस्पर प्रेम, सौहार्द, समन्वय एवं उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करे जिससे संगठन समाज के लिए प्रेरणास्रोत बन सके।

समारोह में परामर्शक बद्रीलाल पितलिया, सतीशकुमार जैन, उदयलाल कटारिया, जुगराज सोलंकी, सभा के अध्यक्ष प्रकाशचंद बाबेल, ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष गौतमचंद मुथा, सुरेशचंद दक आदि ने नई टीम को शुभकामनाएं दी। कन्हैयालाल चिप्पड़ ने धन्यवाद दिया और संचालन पूर्व मंत्री विमल पितलिया ने किया।

उच्च न्यायालय ने रोडरेज मामले में न्यायिक अधिकारी के आचरण पर जतायी नाराजगी

बेंगलूरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कथित रोड रेज की घटना में एक न्यायिक अधिकारी के आचरण पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उनका व्यवहार न्यायपालिका के सदस्य के पद की गरिमा के सर्वथा प्रतिकूल था। अदालत ने इस आरोप पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की कि न्यायिक अधिकारी ने अपने आधिकारिक पद का कथित तौर पर इस्तेमाल कर नागरिकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करायी। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने बुधवार को आरोपियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान घटना का सीसीटीवी फुटेज देखा। फुटेज में कथित तौर पर मलूर की प्रधान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गायत्री और उनके पति उनकी निजी कार से आगे निकलने की होड़ करने वाले दोपहिया वाहन सवारों के साथ बहस करते दिखाई दे रहे हैं।

बैंकों को जमा पर एकसमान ब्याज देना होगा : आरबीआई

मुंबई/भाषा। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को बैंकों से कहा कि वे एक ही दिन समान राशि जमा किए जाने पर सभी शाखाओं में एकसमान ब्याज दर प्रदान करें और इस मामले में किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए। केंद्रीय बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के मुताबिक, जमा (डिपॉजिट) पर दी जाने वाली ब्याज दरें (थोक जमा समेत) बैंकों की वेबसाइट पर पहले से घोषित दरों के अनुरूप ही होनी चाहिए। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि किसी बैंक के लिए समान राशि की जमा, जो एक ही दिन स्वीकार की गई हो, उस पर अलग-अलग दरें देना स्वीकार्य नहीं होगा। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों को हर कारोबारी दिन सुबह 10 बजे तक अपनी वेबसाइट पर थोक जमा की ब्याज दरें सार्वजनिक करनी होंगी।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सार्वजनिक सूचना

दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार – 2026

आवेदन/नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार – 2026 के लिए आवेदन/नामांकन 15 मई, 2026 से आमंत्रित किए गए थे तथा आवेदन/नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **31 जुलाई, 2026** निर्धारित की गई थी।

2. सभी इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं एवं आमजन को सूचित किया जाता है कि **राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (Rashtriya Puraskar Portal) पर ऑनलाइन आवेदन/नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 15 अगस्त, 2026 कर दी गई है।**

3. सभी संबंधितों से अनुरोध है कि आवेदन/नामांकन **केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल** https://awards.gov.in पर ही प्रस्तुत करें। **डाक, कूरियर, ई-मेल अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन/नामांकन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।**

4. पुरस्कारों से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्रता मानदंड तथा अन्य आवश्यक जानकारी निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध है:

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग:
https://depwd.gov.in

राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल:
https://awards.gov.in

CBC 38117/11/0006/2627

कावेरी जल बंटवारे पर फैसला लेने का अधिकार केवल सीडब्ल्यूएमए के पास है : द्रमुक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेता टी. के. एस. एलनगोवन ने बृहस्पतिवार को कहा कि कर्नाटक सरकार का कावेरी नदी पर कोई अधिकार नहीं है और जल बंटवारे का फैसला करने का अधिकार केवल कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के पास है।

एलनगोवन ने मेकेदातु बांध परियोजना के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए यह टिप्पणी की। यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब खबरें हैं कि कर्नाटक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को इस आधार पर लौटा दिया गया कि वह कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप नहीं है। द्रमुक नेता ने कहा, ''एक बार न्यायाधिकरण का गठन हो जाने के बाद उसके अधिकार क्षेत्र में कोई अन्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता।'' केंद्र ने 2018 में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद को सुलझाने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) का गठन किया था। इस बोर्ड में नदी के तटवर्ती राज्यों के सदस्यों के अलावा, केंद्र का एक नामित सदस्य भी शामिल है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और कर्नाटक के उनके समकक्ष डी. के. शिवकुमार के बीच कावेरी विवाद पर प्रस्तावित बैठक के बारे में पूछे जाने पर द्रमुक के प्रवक्ता ने इस पहल को ''महज दिखावा'' करार दिया। एलनगोवन ने 'पीटीआई-वीडियो' से कहा, ''कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात करने का क्या फायदा? वह तो मेकेदातु में बांध बनाने के अपने फैसले पर अड़े हुए हैं।'' उन्होंने कहा कि बातचीत करने के बजाय न्यायाधिकरण से अपील की जानी चाहिए कि वह इस बांध के निर्माण पर रोक लगाए। भ्रष्टाचार निरोधक एवं सतर्कता निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए द्रमुक नेता ने कहा कि बालाजी इस घटनाक्रम से बिल्कुल विचलित नहीं हैं। उन्होंने कहा, ''उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। उनका कहना है कि मैं हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूं।'' एलनगोवन ने विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के राज्य सचिव एम. वीरापांडियन के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु के अधिकारों पर जब भी कोई खतरा आएगा, द्रविड़ दल और वामपंथी दल एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। उन्होंने इस रुख से सहमति जताते हुए दोनों दलों की वैचारिक समानता का उल्लेख किया। एलनगोवन ने कहा, ''हम लगभग 50-60 वर्षों तक साथ रहे हैं... वैचारिक रूप से भी हम एक साथ हैं।'' उन्होंने कहा कि दोनों दल तमिलनाडु के लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। 'तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन' द्वारा यह आरोप लगाए जाने के मुद्दे पर कि सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा पाठ्यक्रमों की 151 सीटों में से सात सीटें अखिल भारतीय कोटे में चली गईं, एलनगोवन ने विरोधियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सीटें बचाने के लिए ठोस कदम उठाने के बजाय विरोधी बिना किसी आधार के इस चूक के लिए द्रमुक को दोषी ठहरा रहा है। करूर भगदड़ मामले में मृतकों के 41 परिजनों को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय का रुख किए जाने के प्रस्ताव पर एलनगोवन ने कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां केवल तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (टीएनपीएससी) और रोजगार कार्यालयों के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान है, लेकिन दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। इस बीच, तमिलागा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार को झटका देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पिछले वर्ष करूर में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया था। अदालत ने कहा कि इससे भविष्य में इसी प्रकार की मांगों की बाढ़ आ जाएगी। न्यायमूर्ति सी. वी. कार्तिकेयन और न्यायमूर्ति आर. शक्तिवेल की खंडपीठ ने कहा कि सरकारी विभागों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अनेक अन्य लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा।

तमिलनाडु सरकार ने अल नीनो के प्रभाव की निगरानी, आकलन के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। तमिलनाडु सरकार ने मजबूत 'अल नीनो' के संभावित प्रभावों की वैज्ञानिक आधार पर निगरानी एवं आकलन करने तथा उपयुक्त एहतियाती एवं आपदा प्रबंधन उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति गठित करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की।

समिति में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, तटीय संसाधन प्रबंधन और शहरी बुनियादी ढांचे समेत विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ शामिल हैं। यह कदम राजस्व प्रशासन के अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त की उस चेतावनी के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि 2026 में भीषण 'अल नीनो' विकसित होने की आशंका बहुत अधिक है।

नतीजतन, दक्षिण-पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम हो सकती है, जिससे कावेरी नदी में पानी की आवक और सिंचाई सुविधाओं पर असर पड़ सकता है। सरकार ने कहा कि इसके अलावा, पूर्वोत्तर मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश और बाढ़ जैसी गंभीर मौसम की घटनाओं की आशंका है। इसलिए, मजबूत अल-नीनो से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर तमिलनाडु आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंसी (टीएनडीआरआरए) को सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति बनाने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार, 28 जुलाई को एक सरकारी आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव/राजस्व प्रशासन आयुक्त और राज्य राहत आयुक्त, चेपॉक, समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। सरकारी आदेश में कहा गया, यह समिति बारिश और सूखे की स्थिति पर नजर रखेगी, जोखिम वाले इलाकों की पहचान करेगी और तमिलनाडु आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंसी को शुरुआती चेतावनी प्रणालियों के बारे में सलाह देगी। समिति संवेदनशील इलाकों में सूखे और बाढ़ से निपटने के उपायों पर सलाह देगी, ताकि किसी भी तरह की आपदा का सामना करने के लिए समय रहते पूरी तैयारी सुनिश्चित की जा सके। यह समिति टीएनडीआरआरए में 2026-27 और 2027-28 की अवधि के लिए काम करेगी।

तमिलनाडु शराब घोटाला

डीवीएसी की जांच तेज होने के बीच खुदरा शराब बिक्री के निजीकरण की चर्चा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। तमिलनाडु में करोड़ों रुपये के कथित शराब घोटाले की जांच तेज होने और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की कथित संलिप्तता के आरोप सामने आने के बीच राज्य में शराब की खुदरा बिक्री के निजीकरण की चर्चा शुरू हो गई है।

सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के एक सूत्र ने संकेत दिया कि राज्य सरकार शराब की खुदरा बिक्री पर अपना एकाधिकार समाप्त कर कड़े नीतिगत नियंत्रण के साथ निजी क्षेत्र को इसमें प्रवेश की अनुमति देने पर विचार कर सकती है। यह सुझाव ऐसे समय सामने आया है जब सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने वर्ष 2021 से 2025 के बीच द्रमुक शासनकाल में टासमैक (तमिलनाडु राज्य विपणन निगम) के बार लाइसेंस, परिवहन ठेकों, खरीद और अन्य संबंधित कार्यों में कथित मिलीभगत की जांच तेज कर दी है।

जांच का दायरा वरिष्ठ नेताओं, नौकरशाहों, शराब बनाने वाली इकाइयों और बॉटलिंग सहित संबंधित कार्यों तक फैला है, जिन पर निविदा प्रक्रिया में हेराफेरी कर अवैध रूप से धन अर्जित करने का आरोप है। इस बीच, मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को भ्रष्टाचार के मामले में सेंथिल बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ आवश्यक है।

डीवीएसी ने 29 जुलाई को राज्यभर में करीब 45 स्थानों पर सेंथिल बालाजी से जुड़े परिसरों पर एक साथ छापेमारी की थी। एजेंसी ने औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज कर बालाजी, टासमैक के पूर्व प्रबंध निदेशक एस. विसाकन, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधकों और उनके सहयोगियों को नामजद किया है। उन पर वर्ष 2021 से 2025 के दौरान मिलीभगत और अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और डीवीएसी का आरोप है कि परिचालन व्यय बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने, फर्जी खरीद, तथा सरकारी शराब विक्रेता टासमैक से अधिक आपूर्ति आदेश हासिल कर करीब 1,000 करोड़ रुपये की अवैध धनराशि जुटाने की संगठित व्यवस्था बनाई गई।

टीवीके के एक सूत्र ने कहा कि सरकार को भ्रष्टाचार समाप्त करने और राजकोष को होने वाले नुकसान को रोकने के अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। इसके लिए कड़ी सरकारी निगरानी के साथ निजी कंपनियों को शराब की खुदरा दुकानें संचालित करने की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने द्रमुक नेता सेंथिल बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

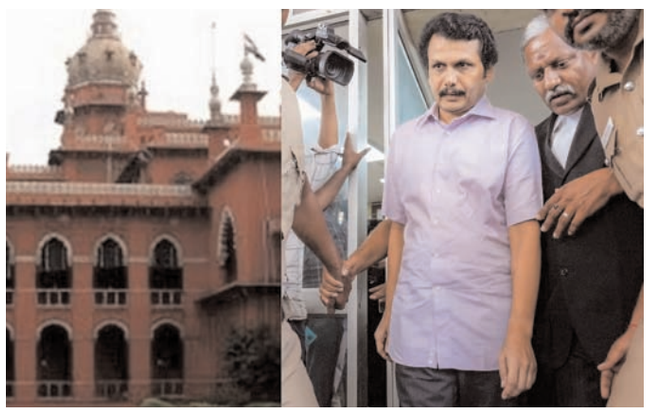

चेन्नई/भाषा। मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन एवं सतर्कता निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा दर्ज तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टासमैक) घोटाला मामले में पूर्व मंत्री और द्रमुक नेता वी. सेंथिल बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति जी. के. इलंथिरैयन ने सेंथिल बालाजी पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के अभियोजन पक्ष के आरोपों का हवाला देते हुए कहा कि मामले की जांच के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी संख्या-1 सेंथिल बालाजी के करीबी सहयोगी रहे सभी अधिकारियों ने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया, आपराधिक साजिश रची और विभिन्न अपराध किए। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों ने हेरफेर के विभिन्न तरीकों से अनुचित लाभ प्राप्त किया और सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया। भ्रष्टाचार निरोधक एवं सतर्कता निदेशालय (डीवीएसी) ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि सेंथिल बालाजी ने टासमैक के कामकाज में हेरफेर करने के लिए आपराधिक साजिश रची। इसके तहत बार लाइसेंस और परिवहन ठेकों की निविदाओं में धांधली की गई, कुछ चुनिंदा शराब निर्माताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जिससे शराब की कीमतें बढ़ीं और सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान हुआ। डीवीएसी ने इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सेंथिल बालाजी, टासमैक के पूर्व प्रबंध निदेशक एस. विसाकन और पांच अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में बार लाइसेंस आवंटन, परिवहन ठेकों तथा कुछ डिस्टिलरी और बॉटलिंग कंपनियों द्वारा कथित फर्जी एवं बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए लेनदेन के जरिए धन के गबन, खरीद प्रक्रिया और निविदा प्रक्रिया में हेरफेर के आरोप लगाए गए हैं। अन्य पांच आरोपियों में सेंथिल बालाजी के करीबी सहयोगी राथेश राज षणमुगावेल और एस. कार्तिक (उर्फ मुलानूर कार्तिक), उनके पूर्व निजी सहायक भास्कर तथा टासमैक के पूर्व अधिकारी आर. रामदुरई मुरुगन और आर. पनीरसेल्वम शामिल हैं। प्राथमिकी में ''करूर गैंग'' नामक एक कथित संगठित गिरोह के संचालन का उल्लेख किया गया है, जिस पर कार्तिक का नियंत्रण होने का आरोप है। आरोप है कि यह गिरोह करूर जिले के सभी शराब बार संचालित करता था और अधिकारियों पर दबाव डालकर पूरे तमिलनाडु में अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को बार लाइसेंस आवंटित कराता था। प्राथमिकी में करोड़ों रुपये के एक सुनियोजित नकद कमीशन तंत्र का भी उल्लेख किया गया है। इसके तहत बोतल आपूर्ति करने वाली कंपनियां डिस्टिलरी के नाम पर फर्जी या बढ़ा-चढ़ाकर बिल बनाती थीं। प्राथमिकी के अनुसार, टासमैक की खुदरा दुकानों पर उपभोक्ताओं से अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक राशि व्यवस्थित तरीके से वसूली जाती थी। सामान्य शराब की प्रत्येक बोतल पर 10 रुपये से 100 रुपये और विदेशी शराब पर 500 रुपये तक अतिरिक्त वसूले जाते थे। सेंथिल बालाजी तमिलनाडु विधानसभा में कोयंबटूर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

टीवीके सरकार के लिए ढाल की तरह काम करेगी एमडीएमके: वाइको

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एमडीएमके) प्रमुख वाइको ने कहा कि अगर कोई भी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश करेगा, तो उनकी पार्टी ढाल और तलवार बनकर उन कोशिशों को नाकाम कर देगी।

एमडीएमके नेता ने यह भी कहा कि टीवीके कभी भी अपने धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी और न ही भाजपा की ओर झुकाव रखेगी।

वाइको ने बुधवार को यहां एक कार्यक्रम में कहा, ''मैंने टीवीके के संस्थापक सी. जोसेफ विजय से कहा कि उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं जिस भी गठबंधन में रहा हूं, उसकी जीत दिलाने में प्रमुख कमांडरों में से एक रहा हूं। आज मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर कोई आपकी सरकार के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश करेगा, तो एमडीएमके उन कोशिशों को विफल करने के लिए ढाल और लड़ने के लिए तलवार का काम करेगी।''

विपक्षी दलों द्वारा टीवीके सरकार को गिराने की कोशिश किए जाने संबंधी खबरों का जिक्र करते हुए एमडीएमके नेता ने कहा, ''दिवास्वप्न मत देखिए। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, अगर ऐसी राजनीतिक स्थिति आती है, तो टीवीके के नेतृत्व वाला गठबंधन 234-सदस्यीय विधानसभा में कम से कम 180 सीट जीतेगा। आपको (विपक्षी दलों को) करारी हार का सामना करना पड़ेगा, आपकी राजनीतिक पहचान खत्म हो जाएगी और आप शून्य पर पहुंच जाएंगे।''

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कावेरी मुद्दे पर दो अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई

नयी दिल्ली/बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने कावेरी जल बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा के लिए दो अगस्त को बेंगलूरु स्थित अपने आधिकारिक आवास 'कृष्णा' पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसके तहत अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक कावेरी का पानी छोड़ा जाना है।

शिवकुमार ने नयी दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, कावेरी जल मुद्दे पर रविवार (दो अगस्त) को मेरे आवास 'कृष्णा' पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कर्नाटक भवन में संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कावेरी नदी बेसिन क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है।

शिवकुमार ने कहा, हमने इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रियों प्रह्लाद जोशी और वी. सोमन्ना के साथ-साथ सांसदों - जगदीश शेट्टार और बसवराज बोम्मई- से भी चर्चा की है। वे राज्य के हितों के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय द्वारा कर्नाटक के बजाय केंद्र सरकार से संपर्क करने की सलाह दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, मैं इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। शिवकुमार ने कहा, हमारी एक-दूसरे से लड़ने में कोई रुचि नहीं है। देश का एक कानून है, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। पूरे देश को एक साथ मिलकर काम करना होगा।

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भाजपा नेताओं की आलोचना का जवाब देते हुए शिवकुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा और उनके बेटे एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी. वाई. विजयेंद्र पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने याद दिलाया कि येदियुरप्पा ने बिना मंत्रिमंडल के ही सरकार चलाई थी।

कन्नड़ फिल्म जगत और किसान संगठनों ने तमिलनाडु के लिए कावेरी जल छोड़ने का किया विरोध

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (केएफसीसी), कन्नड़ फिल्म उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और किसान संगठनों ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने का विरोध करते हुए कहा कि राज्य को सबसे पहले अपनी पेयजल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस बीच, कर्नाटक को झटका देते हुए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने बृहस्पतिवार को राज्य की अपील खारिज कर दी और कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) की उस सिफारिश को बरकरार रखा, जिसमें कर्नाटक को अगले 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी तमिलनाडु के लिए छोड़ने का निर्देश दिया गया है।

केएफसीसी की अध्यक्ष और अभिनेत्री जयमाला ने कहा कि कन्नड़ फिल्म जगत ने हमेशा उन अवसरों पर किसानों का साथ दिया है, जब भी कर्नाटक की भूमि, जल और भाषा पर कोई संकट आया है। उन्होंने कहा कि कावेरी मुद्दे पर भी फिल्म उद्योग जगत किसानों के साथ एकजुट होकर खड़ा रहेगा।

जयमाला ने कहा, हम हमेशा किसानों के साथ रहे हैं। यदि हमारी भाषा, लोग, भूमि और पानी सुरक्षित रहेंगे, तभी हमारा अस्तित्व रहेगा। जब भी इन पर कोई खतरा आएगा, हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे। फिल्म निर्माता सा. रा. गोविंदु ने कहा कि कन्नड़ फिल्म चैंबर इस मुद्दे पर कन्नड़ संगठनों और किसान समूहों द्वारा लिये जाने वाले हर निर्णय का समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि जब कर्नाटक स्वयं पेयजल संकट का सामना कर रहा है, तब तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। गोविंदु ने कहा, तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारे पास पीने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है, जबकि तमिलनाडु तीसरी फसल के लिए पानी मांग रहा है। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि क्या यह उचित है। गोविंदु ने 1991 के कावेरी जल विवाद का उल्लेख करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. बंगारप्पा द्वारा जारी अध्यादेश का हवाला दिया और मौजूदा सरकार से कर्नाटक के हितों की रक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार राज्य के किसानों के हितों की रक्षा करेंगे और मेकेदातु परियोजना को आगे बढ़ाएंगे।

इससे पहले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को खारिज करने का अनुरोध किया था। इस परियोजना का उद्देश्य बेंगलूरु शहर को पेयजल उपलब्ध कराना है।

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई-निविदा सूचना
संख्या 116/26-27
पत्रांक: 128-W/Provision/AC/Renovation wards/BKN/2026 दिनांक : 27.07.2026
मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर भारत के राष्ट्रपति की ओर से इच्छुक ठेकेदारों से निम्न लिखित कार्य के लिए दिनांक 17.08.2026 को 15.00 बजे तक खुली ई - निविदा आमंत्रित करते है :- **निविदा संख्या :** 116 **कार्य का नाम व स्थान :** सहायक मण्डल इंजीनियर- मुख्यालय/ बीकानेर के अन्तर्गत मण्डल चिकित्सालय, लालगढ में वार्ड और टॉयलेट का नवीनीकरण, मरीजों के लिए वेटिंग हॉल की व्यवस्था और AC, मॉड्यूलर OT आदि की व्यवस्था से जुड़े सिविल इंजीनियरिंग के काम। **अनुमानित लागत मूल्य :** Rs. 56563899.23 **धरोहर राशि :** Rs. 1131300.00 **नोटः-** अन्य शर्ते रेलवे की वेब साइट **www.ireps.gov.in** पर देखी जा सकती है। **1099-CQ/26**
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई-निविदा सूचना
सं. एसएण्डटी -जेयू-17-2026-27
भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए मंडल रेल प्रबन्धक/सं.व.दू.उ.प.रे.,जोधपुर द्वारा निम्न लिखित सिगनलिंग एवं टेलीकॉम सम्बन्धी कार्य हेतु मुहरबंद ई निविदाएं आमंत्रित की जाती है। **1. कार्य का नाम :** उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के 64 ब्लॉक सेक्शन में UFSBI के विभिन्न कंपोनेंट्स/पुर्जो की विश्वसनीयता में सुधार और उनके बनाए रखने की व्यवस्था/व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध का कार्य। **2. कार्य की अनुमानित लागत :** रुपये 3,31,76,064/- **3. ई निविदा जमाकर्ता कार्यालय का पूर्ण पता :** वरि. मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी. मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय हरीश जौशी मार्ग जोधपुर **4. बयाना राशि (Bid Security) :** रूपये 663500/- **5. ई निविदा प्रपत्र जमा कराने एवं खुलने की तारीख व समय :** 21.08.2026 को 15.00 बजे तक। तथा ई टेंडर ऑन लाईन आई आर ई पी एस पर 15.00 बजे बन्द होने के तुरन्त बाद खोली जायेगी। **6. वैब साईट विवरण एवं नोटिस बोर्ड व कार्यालय जहाँ से टेण्डर का विवरण देखा जा सकें। एवं खरीद की जा सकें। :** www.ireps.gov.in **नोटः-** यह एक ई टेण्डर हैं इसलिए इसमें भाग लेने के लिए ठेकेदार ई टेण्डरिंग के द्वारा उल्लेखित वैब साईट पर टेण्डर डाले। **1101-CQ/26**
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

राजस्थान में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी : गहलोत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में कुशासन का माहौल है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्य में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा, राजस्थान में जो सरकार चल रही है उसकी चर्चा हर घर में, हर गांव में है। अगर कुशासन की ऐसी ही स्थिति बनी रही तो नुकसान जनता को है। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जनता को सुशासन देने की अपील की। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि आप सुशासन दो....पांच साल राज करो...हमें एतराज नहीं। अगली बार तो हमारा सत्ता में आना निश्चित है...हम जानते हैं कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, पर कम से कम पांच साल जनता के काम होने चाहिए। प्रश्नपत्र लीक रोधी कानून में संशोधन करने वाले विधेयक के लोकसभा से पारित होने पर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, ये विधेयक तो केंद्र सरकार के लिए 'फेस सेविंग' वाली बात है। जो वादा किया था उसको निभाना था। मैं समझता हूं कि अगर वे विपक्षी दलों से सलाह करके लाते तो और अच्छा विधेयक ला सकते थे।

इस बीच, पूर्व मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल के साथ गहलोत से मुलाकात की। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस और आदिवासी समाज का रिश्ता आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक बेहद मजबूत और आत्मीय रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदैव आदिवासी समाज के हक और सम्मान के लिए संघर्षरत रही है और आगे भी रहेगी।

महिला स्वास्थ्य की दिशा में समग्र दृष्टिकोण से कार्य करने की आवश्यकता : राज्यपाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर/कोटा, 30 जुलाई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमें उन्हें शिक्षा से जोड़ना होगा। महिलाएं सशक्त होंगी तो समाज विकसित होगा और राष्ट्र भी सशक्त बनेगा। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करने के लिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की सराहना की और महिला स्वास्थ्य की दिशा में समग्र दृष्टिकोण से कार्य करने पर बल दिया। राज्यपाल बागड़े गुरुवार को कोटा के सिआम ऑडिटोरियम में कृषि विश्वविद्यालय कोटा एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'स्वस्थ एवं शिक्षित महिला सशक्त राष्ट्र' विषेयक दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य एवं उनकी शिक्षा पर आधारित चर्चा समाज एवं राष्ट्र के विकास में उपयोगी सिद्ध होगी।

राज्यपाल ने कहा कि पहले नौकरियों में महिलाओं की संख्या काफी कम होती थी, लेकिन आज विभिन्न कार्यालयों में नौकरीपेशा महिलाओं का प्रतिशत अच्छा है। विभिन्न परीक्षा परिणामों में छात्राएं बाजी मार लेती हैं और उनका उत्तीर्ण प्रतिशत भी छात्रों के मुकाबले अधिक रहता है। उन्होंने इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की धर्मपत्नी श्रीमती सुधा मूर्ति एवं इन्दौर की कमला भागवत का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और समाज में नाम रोशन किया। बागड़े ने स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का आह्वान किया कि बच्चों के बुद्धि कौशल में वृद्धि करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करें। कक्षा में जाने से पहले शिक्षक स्वयं अध्ययन कर अपनी नॉलेज बढ़ाएं और वह ज्ञान बच्चों तक पहुंचाएं। उन्होंने आज की युवा पीढ़ी को आत्मविश्वास बढ़ाने तथा अपनी क्षमताओं का विकास कर जीवन में आगे बढ़ने को कहा।

बागड़े ने कहा कि भारतीय टेलेंट की आज विश्व में अलग पहचान है। अमेरिका एवं जर्मनी जैसे देश हमारे युवाओं को पढ़ाई के साथ जॉब का भी ऑफर दे रहे हैं। बचपन से ही बौद्धिक क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देकर हम हमारे युवाओं की काबिलियत का लोहा पूरे विश्व में मनवा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि महिलाएं परिवारों में संतुलन कायम करने, सामाजिक सरोकारों को निभाने के साथ ही रिश्तों को भी बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। वे सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति की वाहक हैं। उन्होंने उपस्थित महिलाओं का आह्वान किया कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉ. अनूप कोठारी ने कहा कि महिला स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए, क्योंकि महिला स्वस्थ होगी तो पूरा परिवार स्वस्थ होगा। साथ ही, महिला सशक्त होगी तो परिवार भी सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि कई बार परिवार का ध्यान रखते-रखते अपने स्वयं की स्वास्थ्य की चिंता नहीं करती और वे व्याधियों की जकड़ में आ जाती हैं, ऐसे में स्वस्थ खानपान और स्वच्छता पर ध्यान देते हुए उनके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी चर्चा की जानी चाहिए। इस अवसर पर राज्यपाल एवं अन्य अतिथियों ने कार्यशाला की स्मारिका सारांश पुस्तिका का विमोचन किया। बागड़े ने सिआम ऑडिटोरियम परिसर में आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और ऑर्गेनिक उत्पादों के बारे में जानकारी ली।

पशुपालन एवं गोपालन मंत्री ने पाली में ली समीक्षा बैठक, लाभार्थियों को बांटे पट्टे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को पाली जिले की सुमेरपुर नगरपालिका परिसर में विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री कुमावत ने आमजन की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को बेहद गंभीरता से लिया और उनके त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए।

मंत्री जोराराम कुमावत ने आमजन को राहत पहुंचाने के लिए शहर में जलापूर्ति को पूरी तरह सुचारू बनाने और हर घर तक पानी पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने पीडब्लयूडी के अधिकारियों को शहर की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों का तत्काल रख-रखाव और मरम्मत कार्य शुरू करने को कहा। नगर पालिका क्षेत्र में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को तुरंत दुरुस्त करने के आदेश दिए।मानसून सत्र के मद्देनजर मंत्री कुमावत ने मौसमी बीमारियों को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने क्षेत्र में मच्छरों के पनपने से होने वाले संभावित रोगों (जैसे डेंगू, मलेरिया) की रोकथाम के लिए पूरे सुमेरपुर शहर में नियमित रूप से फोगिंग करवाने के सख्त निर्देश नगर पालिका प्रशासन को दिए। समीक्षा बैठक में मानसून के दौरान आमजन को राहत देने और शहरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।बैठक में मंत्री कुमावत ने कहा- शहर के सभी प्रमुख नालों की नियमित सफाई की जाए। 'कचरा पॉइंट्स' से समय पर कचरा उठाया जाए और घर-घर कचरा संग्रहण (डूर-टू-डोर कलेक्शन) व्यवस्था को शत-प्रतिशत प्रभावी बनाया जाए। कुमावत ने कहा कि बारिश के दौरान किसी भी क्षेत्र में पानी का भराव न होने पाए। इसके लिए जल निकासी के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और सीवरेज लाइनों की निरंतर सफाई सुनिश्चित की जाए। कुमावत ने कहा कि बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई और टूटी सड़कों की तुरंत पहचान कर उनकी युद्धस्तर पर मरम्मत (पैच वर्क) कराई जाए ताकि आवागमन सुगम हो सके। उन्होंने कहा- सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों में सफाई व्यवस्था को चाक-चौबंद रखा जाए। मंत्री ने कहा कि सफाई और विकास कार्यों की पारदर्शिता तथा निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से डिजिटल मॉनिटरिंग (कंट्रोल रूम द्वारा निगरानी) को मजबूत किया जाए। मंत्री कुमावत ने अधिकारियों को हिदायत दी कि सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए ताकि धरातल पर परिणाम नजर आएं।

बैठक के पश्चात कैबिनेट मंत्री ने नगरपालिका परिसर में ही संचालित हो रहे 'शहरी सेवा शिविर' का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं को देखा और अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान मंत्री के हाथों विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ और प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

आधुनिक तकनीक का उपयोग कर कम भूमि पर अधिक फसल ले सकते हैं किसान : बागड़े

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को कोटा के जाखोड़ा स्थित श्रीरामशान्ताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन किया और केन्द्र द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा देने एवं कृषकों को प्रशिक्षण देने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। बागड़े ने श्रीरामशान्ताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र में अनुसंधान से जुड़े किसानों के साथ चर्चा के दौरान कहा कि आज के समय में कृषि भूमि कम हो रही है, ऐसे में आधुनिक कृषि पद्धतियों का उपयोग कर कम भूमि पर अच्छी फसल ली जा सकती है। उन्होंने किसानों को खेती के नए तरीके- शेडनेट, पॉली हाउस आदि के उपयोग से सब्जियां उत्पादित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। जैविक खाद का उपयोग कर भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखते हुए फसल एवं अन्न उत्पादित करें ताकि हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक रहे। उन्होंने रासायनिक खाद के विकल्प के रूप में गोबर का उपयोग करने की सलाह दी।

राज्यपाल ने कहा कि किसानों को उन्नत कृषि तकनीक एवं जैविक खेती के बारे में जानकारी देने की दिशा में श्रीरामशान्ताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। राज्यपाल बागड़े ने अनुसंधान केन्द्र के हर्बल गार्डन, वेजिटेबल ब्लॉक, सरल कम्पोस्टिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो बायोलॉजी लैब, कीट विज्ञान प्रयोगशाला एवं गौशाला का अवलोकन किया। राज्यपाल ने गौशाला में गायों को हरा चारा भी खिलाया।

बागड़े ने संस्थान परिसर में बेलपत्र का पौधा भी लगाया। गोयल समूह के ताराचंद गोयल ने बूंद-बूंद पानी के उपयोग तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने के संबंध में किसानों को श्रीरामशान्ताय केन्द्र द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी।

पुनर्वास एवं लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण को दें सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्य सचिव

जयपुर,। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि सिलिकोसिस एक लाइलाज बीमारी है। इसकी गंभीरता को देखते हुए इससे जुड़े हुए सभी विभाग प्रभावित मरीजों के उपचार, पुनर्वास एवं राहत संबंधी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र मरीज तक समयबद्ध चिकित्सा सहायता, आर्थिक राहत एवं पुनर्वास का लाभ पहुँचाना सुनिश्चित किया जाएं।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) नीति, 2019 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में गठित राज्य स्तरीय न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) क्रियान्वयन समिति की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि सिलिकोसिस से अत्यधिक प्रभावित जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रोगियों की एक्स-रे स्क्रीनिंग की समुचित मैपिंग की जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मरीज को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं, नियमित परामर्श एवं फॉलो-अप उपलब्ध कराया जाए तथा सभी मरीजों की भी मैपिंग सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खान एवं श्रम विभाग को लंबित सहायता एवं क्लेम प्रकरणों का विशेष अभियान चलाकर शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिलिकोसिस उन्मूलन एवं प्रभावितों के कल्याण के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (झचण) स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सिलिकोसिस के कारणों, बचाव के उपायों तथा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सहायता योजनाओं के संबंध में व्यापक जनजागरूकता फ़ैलाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने खनन उद्योगों में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए अपनाए जा रहे उपायों की समीक्षा करते हुए खान विभाग को सिलिकोसिस बीमारी के लिए उच्च जोखिम वाले खनन एवं संबंधित उद्योगों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा मानकों का प्रभावी अनुपालन करवाते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

भाजपा सरकार के दावों को नीति आयोग के सूचकांक ने किया उजागर : गहलोत

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि नीति आयोग के सूचकांक ने भाजपा सरकार के दावों और प्रदेश की जमीनी हकीकत के बीच अंतर को उजागर कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि वित्तीय स्थिति, संस्थागत माहौल और कारोबारी पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े प्रमुख संकेतकों में राजस्थान की स्थिति कमजोर हुई है। गहलोत ने कहा कि वित्तीय स्थिति के मामले में राजस्थान 17 राज्यों में 15वें स्थान, संस्थागत माहौल में 13वें स्थान और कारोबारी माहौल एवं बुनियादी ढांचे के मामले में 12वें स्थान पर है।

राजस्थान में दो लाख से अधिक किसान कर रहे हैं प्राकृतिक खेती

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान में दो लाख से अधिक किसान लगभग 91 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार ढाई लाख किसानों को जोड़कर एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने की दिशा में काम कर रही है, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हुए टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत राज्य में अब तक 2,380 क्लस्टर (संकुल) बनाए जा चुके हैं जो आंध्र प्रदेश के बाद देशभर में सर्वाधिक है। इन क्लस्टर से राज्य के दो लाख 12,346 किसान जुड़े हैं और यह संख्या आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे अधिक है। साथ ही, अब तक राज्य के लगभग 91,166 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाई जा चुकी है, जो राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करती है।

मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 तक लगभग 49 करोड़ 97 लाख रुपये का व्यय किया गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को नई दिशा देने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। राज्य में 50 हजार किसानों को गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के माध्यम से जैविक खाद उत्पादन के लिए 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। जोधपुर, कोटा और उदयपुर में 'ऑर्गेनिक फूड मार्केट' स्थापित किए जा रहे हैं जिससे

किसानों को जैविक उत्पादों का बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा।

इसी तरह राज्य सरकार पारंपरिक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैलों से खेती करने वाले किसानों को 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 2,856 करोड़ रुपये का अनुदान राज्य की गोशालाओं को दिया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में 'सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर नैचुरल फार्मिंग' की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो अनुसंधान, प्रशिक्षण और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा। प्राकृतिक कृषि ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें प्रकृति के अनुरूप खेती की जाती है तथा मिट्टी, जल, जैव विविधता और सूक्ष्मजीवों के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने पर विशेष बल दिया जाता है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन 25 नवंबर, 2024 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना तथा किसानों की आय बढ़ाना है। यह मिशन केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रमाणन और विपणन की समग्र सुविधा भी उपलब्ध कराता है। इस मिशन के तहत देशभर में 527 कृषि विज्ञान केंद्र, 76 कृषि विश्वविद्यालय, 194 स्थानीय प्राकृतिक खेती संस्थान तथा 18 उत्कृष्टता केंद्र मिशन अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़े एनएसयूआई के कार्यकर्ता

जयपुर। छात्रसंघ चुनाव बहाल नहीं किए जाने और जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के तीन कार्यकर्ता बृहस्पतिवार सुबह जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़ गए। प्रदर्शनकारियों की पहचान विजय पाल कुड़ी, वियोना जाट और कोशिन खान के रूप में हुई है। उन्होंने गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित पानी की टंकी पर चढ़ कर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस और सिविल प्रशासन के अधिकारियों ने तीनों कार्यकर्ताओं को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया। एहतियात के तौर पर टंकी के चारों ओर एक सुरक्षा जाल भी लगाया गया है, ताकि यदि वे कूदें तो उन्हें सुरक्षित बचाया जा सके।

करीब 51 वर्ष पहले रिलीज हुई बेहद लोकप्रिय हिंदी फिल्म 'शोले' में धर्मेंद्र द्वारा निभाए के किरदार वीरू के पानी की टंकी पर चढ़ने के दृश्य के बाद इस तरह विरोध जताने का चलन बढ़ा। उसके बाद से विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों द्वारा ऊंची इमारतों, बिजली के खंभों, मोबाइल टावरों और पानी की टंकियों पर चढ़कर विरोध जताने की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रही हैं। बुधवार को भी उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के छात्रों ने परीक्षाएं कराने में कथित देरी के विरोध में देहरादून में पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया था। इसके बाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने छात्रों से बातचीत की थी। कांग्रेस से संबद्ध संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो बयान में कहा कि जब तक उनकी मांग मान नहीं ली जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा।

नीट प्रश्नपत्र तैयार व अनुवाद कराने का काम एक ही समूह के शिक्षकों को देने से गड़बड़ी हुईः सूत्र

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2026 में प्रश्नपत्र तैयार करने और उसके अनुवाद का काम एक ही समूह के लोगों से कराए जाने की वजह से संभवत: परीक्षा की गोपनीयता से समझौता हुआ। सूत्रों ने यह बात कही है।

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस बारे में जानकारी अनौपचारिक रूप से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को दे दी है और संभव है कि अपनी औपचारिक सिफारिशों में भी इसका उल्लेख करे। अधिकारियों के अनुसार, नीट-यूजी 2026 में हुई गड़बड़ियां 2024 की अनियमितताओं से पूरी तरह अलग थीं। वर्ष 2024 में एक परीक्षा केंद्र प्रभारी ने कथित तौर पर प्रश्नपत्र लीक करने वाले गिरोह के साथ मिलकर प्रश्नपत्र की चोरी और उसे बांटने में मदद की थी। उन्होंने बताया कि 2024 की जांच के बाद सीबीआई ने प्रश्नपत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, उसकी सुरक्षा और परीक्षा कराने की व्यवस्था में कई बदलाव करने के सुझाव एनटीए को दिए थे, ताकि प्रश्नपत्र की गोपनीयता बनी रहे। सूत्रों के अनुसार, एनटीए ने इन सुझावों को 2025 और 2026 की नीट परीक्षा में लागू किया, इसलिए तकनीकी रूप से इस बार कोई प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ। सूत्रों ने बताया कि 2026 की परीक्षा में एनटीए के पैनल में शामिल जिन शिक्षकों को प्रश्नपत्र तैयार करने और मराठी में अनुवाद करने का काम दिया गया था, उनमें रसायन विज्ञान के शिक्षक पी. वी. कुलकर्णी, भौतिकी की शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंधारे और जीव विज्ञान की शिक्षिका मनीषा संजय हवलदार शामिल थीं। आरोप है कि इन लोगों ने अंतिम प्रश्नपत्र के सवाल याद कर लिए और पुणे में अपनी विशेष ट्यूशन कक्षाओं के कुछ चुनिंदा छात्रों को बता दिए। सूत्रों के अनुसार, ये शिक्षक प्रश्नपत्र तैयार करने और उसका अनुवाद करने, दोनों कामों में शामिल थे, तीन मई को हुई परीक्षा से पहले उन्हें अंतिम प्रश्नपत्र लंबे समय तक देखने का मौका मिला। सूत्रों के अनुसार सीबीआई जांच में पता चला कि इस दौरान उन्हें सुरक्षा व्यवस्था वाले माहौल में रखा गया था। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चली। वे हर दिन अपना काम खत्म करने के बाद घर जाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे और अगले दिन फिर ड्यूटी पर लौट आते थे। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने अंतिम प्रश्नपत्र के सवाल याद कर लिए। घर जाकर उन्होंने उन सवालों का एक प्रश्न बैंक तैयार किया और अपने ट्यूशन सेंटर के कुछ चुनिंदा छात्रों को यह कहते हुए दे दिया कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। उन्होंने छात्रों को यह नहीं बताया कि ये आने वाली नीट परीक्षा के असली सवाल हैं।

बंगाल के मुख्यमंत्री ने 'जनता दरबार' लगाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बृहस्पतिवार को अपना साप्ताहिक 'जनता दरबार' लगाया, जिसमें नौकरी चाहने वाले, पेशेवर और आम नागरिक बड़ी संख्या में अपनी शिकायतें सीधे उनके सामने रखने के लिए पहुंचे। इनमें नादिया जिले के कृष्णानगर निवासी वह महिला भी शामिल थी जिसने आरोप लगाया कि उनकी बेटी से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और अक्टूबर 2024 में तेजाब डालकर उसका शव जला दिया गया था।

उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताकर टालने की कोशिश की थी। पीड़ित महिला ने कहा कि परिवार कानूनी दखल के बाद ही प्राथमिकी दर्ज करा सका, लेकिन जांच में 'बहुत कम प्रगति' हुई। महिला ने याद किया कि घटना के बाद अधिकारी (जो तब प्रतिपक्ष के नेता थे) उनके घर पहुंचे थे और परिवार के सदस्यों को मदद का भरोसा दिलाया था। अब जब अधिकारी मुख्यमंत्री हैं, तो मृतका की मां ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आखिरकार न्याय मिलेगा। महिला ने अधिकारी से नए सिरे से जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया। जमीन हड़पने से लेकर सरकारी सेवा के लाभ न मिलने तक की शिकायतों वाले कई अन्य लोग अधिकारी के 'जनता दरबार' में उनसे मिलने का इंतजार कर रहे थे।

जन सुनवाई में एक और महिला ने जाधवपुर से भाजपा विधायक शरबोरी मुखर्जी पर आरोप लगाया कि वह उसकी साड़ी और कपड़ों की दुकान पर जबरदस्ती कब्जा कराने में मदद कर रही हैं। महिला का कहना था कि वह यह दुकान पिछले 30 सालों से चला रही थीं। महिला ने आरोप लगाया कि 12 जून की रात को विधायक के दो साथियों ने दुकान को तोड़ दिया और उस पर कब्जा कर लिया। महिला का कहना था कि भले ही मुखर्जी उस समय मौके पर मौजूद नहीं थीं, लेकिन यह कब्जा उनके समर्थकों ने ही किया था। महिला के अनुसार, अधिकारी ने उनके दिए गए दस्तावेजों की जांच की और उन्हें भरोसा दिलाया कि किसी को भी उनकी दुकान पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करने दिया जाएगा।

कई लोग सीधे उनसे मिलने के लिए राज्य के दूर-दराज के इलाकों और जिलों से पहुंचे थे। याचिकाएं और ज्ञापन लिए लोग मुख्यमंत्री से बातचीत करने के मौके का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने नौ मई को पद संभालने के बाद लोगों से सीधे जुड़ने की पहल के तहत यह कार्यक्रम शुरू किया था। पहला 'जनता दरबार' 18 मई को आयोजित किया गया था।

नकली दवाओं की आपूर्ति करने वाले संगठित गिरोह का भंडाफोड़, छह मुकदमे दर्ज

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नकली और घटिया दवाओं के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने नकली बिल, क्रॉस-बिलिंग और नकली बैंक लेन-देन के जरिए बाजार में नकली दवाओं की आपूर्ति करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि इस मामले में लखनऊ के अमीनाबाद थाने में छह मुकदमे दर्ज किये गये हैं।

एफएसडीए ने नकली दवाओं की आपूर्ति को रोकने के लिए इस महीने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ दवाएं जब्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद इस गिरोह के पीछे के पूरे नेटवर्क को खत्म करना है। एफएसडीए की आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने बताया कि जांच में पता चला कि मिश्रा एसोसिएट्स (अमीनाबाद), मिश्रा मेडिकल एजेंसी (बछरावां, रायबरेली), श्री अशोक फार्मास्यूटिकल्स (अमीनाबाद), भारत फार्मा और एमडीएच फार्मा बिना किसी वास्तविक दवा आपूर्ति के केवल कागज़ों पर 'क्रॉस-बिलिंग' कर रही थीं। उन्होंने बताया कि नकली दवाओं को असली दिखाने की कोशिश में बिना किसी बैंक अंतरण के नकली लेन-देन दिखाए जा रहे थे। जैकब ने बताया कि इन जानकारियों के आधार पर मनीष मिश्रा, आमोद कुमार मिश्रा, सनी कश्यप, देवेंद्र शुक्ला और राहुल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अमीनाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा यह हुआ कि भारत फार्मा और एमडीएच फार्मा के नाम से दिखाई गई फर्म, जिनके जरिए करोड़ों रुपये की दवाओं की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड दिखाया गया था, उनकी दवाओं का कोई वास्तविक भंडार नहीं था। संबंधित मालिकों-अमरीन अहसान और मंताशा ने लिखित बयान दिए कि उनकी फर्म उनकी जानकारी के बिना देवेंद्र शुक्ला द्वारा चलाई जा रही थीं।

एक सरकारी संस्था का दूसरे संस्थान के खिलाफ आरटीआई का इस्तेमाल करना 'बेहद चिंताजनक': सीआईसी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। एक सरकारी संस्था की ओर से दूसरी सरकारी संस्था के खिलाफ सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून का इस्तेमाल किये जाने को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 'बेहद चिंताजनक मामला' करार दिया है। सीआईसी की ओर से यह चिंता तब जताई गई जब केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) से बुनियादी जानकारी पाने के लिए पहले सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून का सहारा लेना पड़ा और बाद में आयोग के पास जाना पड़ा। हाल ही में दिए गए एक आदेश में सूचना आयुक्त विनोद कुमार तिवारी ने इस स्थिति को 'बेहद परेशान करने वाला और 'गंभीर चिंता का विषय' बताया।

उन्होंने कहा कि यह 'सचमुच दुखद' है कि एक वैधानिक आयोग को अपनी ही सुरक्षा जमा राशि के मिलान और धन वापसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए दूसरे वैधानिक आयोग से हस्तक्षेप का अनुरोध करना पड़ा। यह मामला मई 2024 में सीईआरसी के एक अधिकारी द्वारा दायर आरटीआई आवेदन से शुरू हुआ।

मनमोहन सिंह के मामले में न्यायालय का फैसला सत्य की जीत : अश्विनी कुमार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में क्लीन चिट दिया जाना ''सत्य की जीत'' है, लेकिन यह दुखद है कि सिंह यह दिन देखने के लिए इस दुनिया में नहीं हैं।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में मनमोहन सिंह के खिलाफ जारी आपराधिक मामला बंद कर दिया और उन्हें आरोपी के रूप में तलब करने वाला आदेश रद्द कर दिया। कुमार ने एक बयान में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मामले में आया यह फैसला सच्चाई की जीत है।

उन्होंने कहा, ''उच्चतम न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय की पुष्टि करता है, लेकिन यह मामला देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रियाओं को लेकर कई गंभीर सवाल भी खड़ा करता है।'' पूर्व कानून मंत्री का कहना है कि बेदाग ईमानदारी के लिए पहचाने जाने वाले मनमोहन सिंह को अपने जीवनकाल में जिस तरह के 'मीडिया ट्रायल' का सामना करना पड़ा, उससे उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को अपूरणीय क्षति पहुंची। उन्होंने कहा कि अभियोजन की प्रक्रिया ही अपने आप में एक सजा बन गई थी, जिसकी कठोरता अब उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें दोषमुक्त किए जाने के बाद स्पष्ट हो गई है।

कुमार ने कहा, ''यह व्यवस्था पर एक दुखद टिप्पणी है कि डॉ. मनमोहन सिंह अपने नाम से आरोप हटने का दिन देखने के लिए जीवित नहीं रहे। किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध होने से पहले ही दोषी मान लिया जाता है और उसके पास अन्यायपूर्ण आरोपों के खिलाफ प्रभावी राहत का कोई सार्थक उपाय नहीं होता।''

बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री डालने के मामले में आरोप तय किए जाने पर रोक लगाने से अदालत का इनकार

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली की एक अदालत ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी चीजें फेसबुक पर डालने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि अपराध में इस्तेमाल मोबाइल फोन भले ही बरामद नहीं हुआ हो, लेकिन अगर डिजिटल सबूतों से यह साबित होता है कि फेसबुक अकाउंट आरोपी का है, तो मामले की सुनवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

आदित्य बिस्वास की पुनर्विचार याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरविंदर सिंह जग्गी की अदालत सुनवाई कर रही थी। बिस्वास ने उसके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी के तहत आरोप तय करने का निर्देश देने से संबंधित निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। यह धारा बच्चों से संबंधित यौन सामग्री प्रकाशित या प्रसारित किए जाने के मामलों से संबंधित है।

दिल्ली की अदालत ने 27 जुलाई के अपने आदेश में कहा, अगर डिजिटल सबूत, खासकर आईपी लॉग और सब्सक्राइबर की जानकारी से स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया अकाउंट आरोपी के नियंत्रण में था और उसी पर सामग्री डाली गई थी, तो केवल मोबाइल फोन बरामद नहीं होने के आधार पर आरोप तय करने से इनकार नहीं किया जा सकता।

यह मामला दिसंबर 2022 में दक्षिण दिल्ली साइबर पुलिस थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 'नीम बिस्वास' नामक अकाउंट पर 17 सेकेंड का एक वीडियो डाला गया था, जिसमें एक बच्चा अश्लील यौन हरकत करता हुआ दिख रहा था।

आस्था की मिसाल : ट्राइसाइकिल से मचैल माता मंदिर जा रही दिव्यांग महिला, 'दंडवत यात्रा' पर निकला युवक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जम्मू/भाषा। उत्तर प्रदेश की रहने वाली ज्योति नाम की एक दिव्यांग महिला पिछले आठ साल से हाथ से चलने वाली ट्राइसाइकिल के सहारे जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में समुद्र तल से 9,500 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित मचैल माता मंदिर की वार्षिक तीर्थयात्रा कर रही है। वहीं, राज्य के महोबा जिले का रहने वाला सुनील कुमार नामक तीर्थयात्री समुद्र तल से 13,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर तक अपनी 'दंडवत यात्रा' के जरिये सुर्खियां बंटोर रहा है। 'दंडवत यात्रा' सनातन धर्म में एक बेहद कठिन और पवित्र धार्मिक साधना है, जिसमें श्रद्धालु जमीन पर साष्टांग लेटकर शरीर को आगे खिसकाते हुए तीर्थयात्रा पूरी करते हैं। ज्योति और सुनील मचैल माता और अमरनाथ मंदिर की वार्षिक तीर्थयात्रा करने के इच्छुक श्रद्धालुओं के बीच आस्था, हौसले और समर्पण की अटूट मिसाल बनकर उभरे हैं।

ज्योति ने 2015 में एक रेल हादसे में दोनों पैर गंवा दिए थे। वह अपनी मां, पालतू बंदर बजरंगी और पालूत कुत्ते कालू के साथ एक बार फिर मचैल माता मंदिर की दुर्गम यात्रा पर निकली है। ज्योति ने जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले से लगभग दो महीने पहले अपनी ट्राइसाइकिल के जरिये यह तीर्थयात्रा शुरू की थी। वह कहती है, मैं पिछले आठ साल से मचैल माता मंदिर के दर्शन कर रही हूं। मैंने 2018 में पहली बार यह तीर्थयात्रा की थी और तब से हर साल इसी ट्राइसाइकिल के जरिये मचैल माता और बाबा अमरनाथ, दोनों के दर्शन करने जाती हूं। ज्योति के मुताबिक, वह देवी-देवताओं से अपने लिए कुछ नहीं मांगती। वह कहती है, मेरी बस यही प्रार्थना है कि लोग सही रास्ते पर चलें, अपने परिवार का ध्यान रखें और माता रानी का आशीर्वाद उन पर बना रहे।

ज्योति के अनुसार, इस साल 'बजरंगी' और 'कालू' भी उनके साथ तीर्थयात्रा पर आए हैं। उन्होंने बताया कि 'बजरंगी' की मां की बिजली का झटका लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद से वह उसके परिवार का हिस्सा बन गया, जबकि 'कालू' चार महीने से उसके साथ है। किश्तवाड़ जिले की पद्दार घाटी के मचैल गांव में स्थित प्राचीन मचैल माता मंदिर देवी चंडी को समर्पित है, जिन्हें दुर्गा का एक रूप माना जाता है। हिमालय की गोद में बसा यह मंदिर हर साल अगस्त में हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिनमें से ज्यादातर जम्मू क्षेत्र से आते हैं।

इस साल वार्षिक मचैल माता मंदिर तीर्थयात्रा 25 जुलाई को शुरू होनी थी। हालांकि, यह दो दिन की देरी से यानी 27 जुलाई को आरंभ हुई। महोबा निवासी सुनील बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ स्थित पवित्र गुफा मंदिर तक 'दंडवत यात्रा' कर रहे हैं। वह अपनी तीर्थयात्रा के 414वें दिन थर्माकोल की शीट पर पेट के बल रेंगते हुए अनंतनाग पहुंचे। सुनील ने कहा, मैं पवित्र अमरनाथ धाम की 'दंडवत यात्रा' कर रहा हूं। आज मेरी यात्रा का 414वां दिन है। बाबा अमरनाथ ने मुझे बुलाया है। उन्होंने तीर्थयात्रा के दौरान भरपूर सहयोग देने के लिए सुरक्षा बलों का आभार जताया।

गड्ढे में गिरकर जान गंवाने वाले बच्चे के माता-पिता को 16 लाख रु से अधिक मुआवजा देने का आदेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सितंबर 2014 में सीवर के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने के कारण जान गंवाने वाले 10 वर्षीय बच्चे के परिवार को 16 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड को बच्चे की मां और पिता को 16.92 लाख रुपये और नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज देने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से लापरवाही बरती। घटना के समय भागीरथी विहार नहर के पास दिल्ली जल बोर्ड के निर्देश पर सीवर से जुड़ा काम किया जा रहा था। इस दौरान याचिकाकर्ताओं के नाबालिग बेटे की गंदे पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई।

अदालत ने 27 जुलाई के अपने फैसले में कहा, प्रतिवादी ऐसे कदम उठाने में विफल रहे, जिनसे दुर्घटना को रोका जा सकता था। उन्होंने स्पष्ट रूप से लापरवाही बरती। लिहाजा दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिया जाता है कि वे 16,92,511 रुपये की राशि का भुगतान करें। इसके साथ याचिका दायर करने की तारीख से लेकर राशि का भुगतान होने की तिथि तक नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी भुगतान किया जाए।

भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग नीले से भगवा किए जाने से दुखी और आहत हूं : पटनायक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर/भाषा। बीजू जनता दल (बीजेडी) के अध्यक्ष और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बृहस्पतिवार को भारतीय हॉकी टीम की जर्सी के पारंपरिक नीले रंग को बदलकर भगवा किए जाने पर 'गहरी पीड़ा' व्यक्त की। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें अगले महीने नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले एफआईएच विश्व कप में अपनी पारंपरिक नीली जर्सी की जगह भगवा रंग की जर्सी में नजर आएंगी। लगभग एक दशक पहले जब नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री थे, तब ओडिशा सरकार भारतीय हॉकी टीम की प्रायोजक बनी थी।

हॉकी इंडिया द्वारा सोशल मीडिया पर नई जर्सी जारी किए जाने के बाद पटनायक ने 'एक्स' पर एक लंबी पोस्ट में कहा, ''यह जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है कि भारतीय हॉकी टीम की जर्सी के ऐतिहासिक रंग को बदलकर भगवा कर दिया गया है। '' हॉकी इंडिया ने अपने सोशल मीडिया पेज पर नई जर्सी का अनावरण करते हुए कहा कि जर्सी का डिजाइन और रंग एक कहानी बताने और भारत का गौरव दिखाने के लिये है । हॉकी इंडिया ने कहा कि केसरिया रंग साहस, बलिदान और जीत का प्रतीक है । इसने कहा, ''भारत के राष्ट्रध्वज और उगते हुए सूरज से प्रेरित यह जर्सी नई शुरूआत की प्रतीक है।'' हालांकि पटनायक ने इस बदलाव पर चिंता जताते हुए कहा, ''भारतीय हॉकी टीम का प्रतिष्ठित नीला रंग सिर्फ एक रंग नहीं है। यह देश की खेल विरासत से जुड़ी भावना है। दशकों से इस रंग ने हमें उम्मीद, जीत, हार और खेल में उत्कृष्टता की तलाश में एकजुट किया है। ''

हॉकी से अपने भावनात्मक जुड़ाव को याद करते हुए पटनायक ने कहा, ''हम अपनी पुरुष और महिला टीमों के साथ रोए, हंसे, जश्न मनाया और गर्व से खड़े रहे। नीली जर्सी पहनकर हमारी टीमों ने दुनिया के मंच पर राष्ट्रगान बजते समय ओलंपिक पदक जीते हैं। '' स्कूल स्तर पर हॉकी टीम के गोलकीपर रह चुके पटनायक ने कहा, ''नीला रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र से लिया गया है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव और पहचान का प्रतीक है। नीला रंग हर भारतीय का है।'' पटनायक ने याद किया कि जब भारतीय हॉकी टीमों को प्रायोजक मिलने में परेशानी हो रही थी, तब ओडिशा ने इतिहास रचते हुए राष्ट्रीय टीम और इस प्रिय खेल का समर्थन करने वाला पहला और एकमात्र राज्य बनने का गौरव हासिल किया था। उन्होंने कहा, ''दुनिया भर में हर 'उड़िया' (ओडिशा राज्य के वासी) को राष्ट्रीय हॉकी के लिए राज्य के इस योगदान पर गर्व था। 41 साल के लंबे इंतजार के बाद हमारी पुरुष टीम ने ओलंपिक पदक जीता। सिर्फ इसलिए कि ओडिशा में सरकार बदल गई है, हमारी राष्ट्रीय टीम की जर्सी का रंग नहीं बदलना चाहिए। यह बेहद निम्न स्तर की राजनीति है। '' नीली जर्सी के महत्व को बताते हुए पटनायक ने कहा, ''हमारे लिए नीली जर्सी वही महत्व रखती है जो अर्जेंटीना की धारियों वाली जर्सी और ब्राजील की पीली जर्सी का है। यह हमारी यादों में बसी हुई है।''

ऋण धोखाधड़ी मामला : ईडी ने विदेशी बैंक में जमा 94 करोड़ रुपये के लेनदेन पर रोक लगाई

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली स्थित बासमती चावल व्यापार कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ 1,200 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में एक भगोड़े आर्थिक अपराधी के सिंगापुर के बैंक खाते में जमा 94 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लेनदेन पर रोक लगा दी गई है।

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (एपीएफपीएल) के प्रवर्तक और आरोपी करण चानना को अस्थायी रोक आदेश की जानकारी दे दी गई है। बयान में कहा गया है कि भारत द्वारा ब्रिटेन और सिंगापुर के साथ की गई पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) के जरिये और अन्य उपलब्ध माध्यमों से चनाना तक इस आदेश की जानकारी पहुंचाई गई है। बयान के अनुसार, धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है।

चानना ब्रिटेन में रहता है। उसे और कंपनी की सह-प्रवर्तक अनीता डाइंग को फरवरी में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। ईडी के मुताबिक, डाइंग दुबई में रहती है।

अजिंक्य रहाणे मूक योद्धा, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दिखाई अपनी असली क्षमता : प्रवीण आमरे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। भारत के पूर्व बल्लेबाज और अजिंक्य रहाणे के पूर्व कोच प्रवीण आमरे ने बृहस्पतिवार को कहा कि रहाणे एक 'मूक योद्धा' थे जिन्होंने 2020-21 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपने प्रदर्शन और नेतृत्व से अपनी असली क्षमता का शानदार परिचय दिया। भारत के लिए अपना आखिरी मैच खेलने के तीन साल बाद 38 वर्षीय रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने 2011 में पदार्पण करने के बाद 12 वर्षों से अधिक के करियर में 85 टेस्ट, 90 एकदिवसीय और 20 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। आमरे ने पीटीआई वीडियो से कहा, ''हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न टेस्ट में उन्होंने क्या किया था जबकि इससे पहले टीम 36 रन पर आउट हो गई थी।'' उन्होंने कहा, ''उस स्थिति से टीम को संभालना, खुद प्रदर्शन करना, आगे बढ़कर नेतृत्व करना और शतक बनाना... मेरा मानना है कि यही बल्लेबाजी की कला और नेतृत्व की असली पहचान है। जब टीम का मनोबल पूरी तरह गिर चुका था तब वहां से वापसी कर ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर हराना असाधारण उपलब्धि थी।''

आमरे ने कहा, ''अजिंक्य रहाणे हमेशा एक मूक योद्धा रहे क्योंकि उन्हें पता था कि जब भी टीम को उनकी जरूरत होगी, वह उसके लिए मौजूद रहेंगे। उनका पालन-पोषण और उनका रवैया ही ऐसा था। मुझे इस बात पर बेहद गर्व है क्योंकि उनके अधिकांश महत्वपूर्ण प्रदर्शन कठिन परिस्थितियों में आए और यही उनकी बल्लेबाजी की विशेषता थी।''

सुविचार

संतोष सबसे बड़ा धन है। जो मिला है उसका आभार मानें, और आगे बढ़ने का प्रयास करें। कृतज्ञता रखें, मन प्रसन्न रहेगा।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

आधुनिकता के नाम पर नई विकृति

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने विवाह और सहजीवन संबंध के बारे में जो टिप्पणी की है, उससे युवाओं को शिक्षा लेनी चाहिए। भागवत ने सत्य कहा कि विवाह एक ऐसा अनुशासन है, जो धर्म के संस्कार देता है, जबकि सहजीवन संबंध की वास्तविकता पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। उन्होंने जेन जी की मनोदशा के बारे में भी पूर्णत: सत्य कहा कि ये दूसरों की देखादेखी करते हैं, भावुक होते हैं, शांत मन से नहीं सोचते हैं और जो बात सही लगती है, उसी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। सहजीवन संबंध के पीछे शारीरिक आकर्षण मुख्य तत्त्व होता है। जब तक यह बना रहता है, दोनों साथ रहते हैं। जैसे ही आकर्षण खत्म हुआ, दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। पश्चिमी देशों में इसका खूब बोलबाला है। अब कई भारतीय युवा इस रास्ते पर चल पड़े हैं। इसका नतीजा पचास साल बाद जो होगा, सो होगा, लेकिन इसके रुझान आने लगे हैं। अक्सर सहजीवन संबंध भयंकर कड़वाहट के साथ खत्म होते हैं। कई मामलों में महिला-पुरुष को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जब सहजीवन संबंध के एक-दो साल बाद महिला ने पुरुष पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। वहीं, पुरुष ने उस पर धोखा देने का आरोप लगाकर अपना बचाव किया। अदालतें भी ऐसे संबंधों पर चिंता जता चुकी हैं। भारत समेत कई देशों में संयुक्त परिवारों का चलन रहा है। उन्हें प्रगति के नाम पर धीरे-धीरे तोड़ा गया। ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे पश्चिमी कंपनियों की साजिश थी। अगर संयुक्त परिवार होगा तो एक मकान, एक टीवी, एक वाहन, एक टेलीफोन, एक फ्रिज आदि से काम चल जाएगा। बड़े बच्चों के कपड़े बाद में छोटे बच्चों के काम आ सकते हैं। उनकी किताबें छोटे भाई-बहन पढ़ सकते हैं। अगर परिवार टूटेंगे तो सबको अपनी जरूरतों के लिए अलग-अलग चीजें खरीदनी होंगी।

अब इससे एक कदम आगे की तैयारी है! सहजीवन के पीछे कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं होती है। बस, भोगवाद को प्रधानता दी जाती है। यहां संयम की कोई शर्त नहीं है। इसमें आने के बाद भविष्य की परवाह कौन करे? खाएं, पीएं, मौज उड़ाएं। कल किसने देखा है? इस 'कल्चर' ने कई कंपनियों का धंधा खूब चमका दिया है। फिल्मों और वेबसीरीजों ने सहजीवन संबंध को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनके जरिए युवाओं के मन में यह बात बैठाने की पूरी कोशिश की जाती है कि 'सहजीवन संबंध आधुनिकता की निशानी है।' हालांकि, जब इसमें कड़वाहट आती है तो पूरा खामियाजा एकसाथ भुगतने के प्रबल योग बन जाते हैं। माता-पिता को पछतावा होता है कि उन्होंने समय रहते बच्चों को मार्गदर्शन नहीं दिया। एक शख्स ने अपने मामा की आपबीती का वर्णन कुछ इस तरह किया- मामा दिखने में बड़े सीधे लगते थे। वे दो बच्चों के पिता थे। विदेश में उनकी नौकरी लगी तो यह वादा कर चले गए कि कुछ दिन बाद पत्नी-बच्चों को बुला लूंगा। सालभर गुजरने के बावजूद मामा ने उन्हें बुलाने की कोई कोशिश नहीं की। जब कभी परिवार इस बारे में पूछता तो वे कोई और बात शुरू कर देते थे। इस बीच, भांजे ने अपनी नौकरी लगवाने के लिए कई बार आग्रह किया, लेकिन मामा का एक ही जवाब होता था- 'अब यहां वह बात नहीं रही, धंधा मंदा चल रहा है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है।' एक दिन मामी और भांजे ने योजना बनाई। वे अचानक वहां पहुंच गए तो पता चला कि मामा एक महिला के साथ सहजीवन संबंध में रह रहे थे और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उसी पर उड़ा रहे थे। फिर तो भारी हंगामा और रोना-धोना हुआ। वह व्यक्ति बड़ी मुश्किल से स्वदेश लौटा। ऐसी घटना किसी और के साथ न हो, इसके लिए परिवार में खुलकर बात करें और इस विकृति से कोसों दूर रहें।

ट्वीटर टॉक

संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें जयंती वर्ष के अवसर पर, 'समरसता संकल्प अभियान' के तहत वाराणसी से आई समरसता रथ का आज राजस्थान में मातृ शक्ति द्वारा आयोजित कलश यात्रा में भाग लेकर, हमने रविदास जी महाराज को कोटि-कोटि नमन किया।

-दिया कुमारी

जिले के विकास के सफर को तेज करते हुए आज गाजीपुर, जखनियां, मोहम्मदाबाद, सैदपुर, जमानिया, जहूराबाद और जंगीपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 692 करोड़ की 268 जनकल्याण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया।

-योगी आदित्यनाथ

श्रावण मास के पहले दिन मुख्यमंत्री निवास स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में देवों के देव महादेव की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि उनकी कृपा से राजस्थान निरंतर तरक्की, खुशहाली और जनकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे।

-भजनलाल शर्मा

प्रेरक प्रसंग

जीवन का आदर्श

एक बार धारा नगरी के राजा महाराज भोज की राजसभा में दूर-दूर के विद्वान आमंत्रित थे। महाराज भोज ने उन सभी से आग्रह किया, 'आप सभी विद्वान अपने जीवन में घटित कोई आदर्श घटना सुनाएं।' महाराज भोज किसी की भी घटना से प्रभावित नहीं हुए। अंत में, एक दीन-हीन सा विद्वान थोड़ा झिझकते हुए बोला, 'मैं तो इस विद्वत सभा में आने का अधिकारी भी नहीं था, किंतु मेरी पत्नी का बहुत आग्रह था, इसलिए चला आया। यात्रा को ध्यान में रखते हुए मेरी पत्नी ने एक पोटली में मेरे लिए चार रोटियां बांध दी थीं। मार्ग में भूख लगने पर जब मैं एक जगह खाने बैठा, तभी एक कुत्ता मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसके सामने एक रोटी रख दी। वह उसे तुरंत खा गया। इसके बाद मैंने जैसे ही खाने के लिए रोटियों को छुआ, वह फिर से रोटी मिलने की इच्छा से दुम हिलाने लगा। मैंने सभी रोटियां उसके आगे डाल दीं। बस महाराज! यही है मेरे जीवन में हाल ही में घटित सत्य और आदर्श घटना। स्वयं भूखा रहकर एक भूखे जीव को मैंने तृप्त किया। ऐसा करने से जो सुखद अहसास मुझे हुआ, वह मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा।'

सामयिक

बदलता परिदृश्य और आरक्षण की प्रासंगिकता

महेन्द्र तिवारी

मोबाइल : 9989703240

संस्थागत नीतियों और निजीकरण के बढ़ते प्रभाव ने भी इस बहस को एक नया आयाम दे दिया है। आज सरकारी क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है और ज्यादातर रोजगार निजी क्षेत्र में पैदा हो रहे हैं। ऐसे में यह सवाल जोर शोर से उठाया जा रहा है कि क्या निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। कुछ संगठन खुले तौर पर इसकी वकालत कर रहे हैं और उनका तर्क है कि जब देश के संसाधन सभी के हैं तो निजी क्षेत्र को भी सामाजिक न्याय के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

मोबाइल सा विषय है जिसकी तपिश कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। यह एक ऐसा मुद्दा है जो समय-समय पर अपनी राख झटककर फिर से धधक उठता है। वर्तमान समय में एक बार फिर आरक्षण की बहस ने जोर पकड़ लिया है और यह पूरे देश में विमर्श के केंद्र में आ गया है। सड़कों से लेकर संसद तक और चौपालों से लेकर समाचार स्टूडियो तक हर जगह आरक्षण की ही चर्चा है। यह कोई अचानक उठी मांग नहीं है बल्कि इसके पीछे कई तात्कालिक और ऐतिहासिक कारण मौजूद हैं। आज के परिदृश्य में यह बहस सिर्फ इस बात पर नहीं हो रही है कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं बल्कि विवाद का केंद्र यह बन गया है कि इसका स्वरूप कैसा हो इसके दायरे में कौन-कौन आए और इसका वास्तविक लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। यह विषय अब केवल अधिकारों की मांग तक सीमित नहीं है बल्कि यह सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने का एक बड़ा राजनीतिक हथियार भी बन चुका है।

आजादी के बाद जब भारतीय संविधान की रचना हो रही थी तब संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे समतामूलक समाज की कल्पना की थी जिसमें सदियों से पिछड़े और शोषित वर्गों को मुख्यधारा में लाया जा सके। उस समय आरक्षण की व्यवस्था को एक अस्थायी उपाय के रूप में देखा गया था जिसका मूल उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का उत्थान करना था। लेकिन समय बीतने के साथ यह व्यवस्था भारतीय राजनीति की एक स्थायी धुरी बन गई। मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद भारतीय राजनीति में जो भूचाल आया उसने देश की सामाजिक संरचना को गहरे तक प्रभावित किया। तब से लेकर आज तक आरक्षण की परिधि का लगातार विस्तार हुआ है और नई-नई जातियां इस छतरी के नीचे आने की जद्दोजहद कर रही हैं। आज की स्थिति यह है कि आरक्षण का मुद्दा केवल दलितों या आदिवासियों तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अब आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग भी इस व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं।

हाल के दिनों में इस मुद्दे के फिर से तूल पकड़ने का सबसे बड़ा कारण जातीय जनगणना की मुखर होती मांग है। विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन यह तर्क दे रहे हैं कि जब तक देश में यह स्पष्ट नहीं होगा कि किस जाति की कितनी आबादी है तब तक संसाधनों और अवसरों का न्यायसंगत वितरण संभव नहीं है। उनका मानना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के सिद्धांत पर ही नीतियां बननी चाहिए। यह मांग इतनी प्रबल हो चुकी है कि कई राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर इस दिशा में कदम भी बढ़ाए हैं। जातीय जनगणना की इस मांग ने देश की राजनीति में एक नया विमर्श खड़ा कर दिया है और यह स्थापित राजनीतिक समीकरणों को चुनौती दे रहा है। इसके साथ ही कोटे के भीतर कोटे यानी आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर भी एक नई बहस छिड़ गई है। यह तर्क दिया जा रहा है कि आरक्षण का लाभ कुछ चुनिंदा प्रभावशाली जातियों तक ही सिमट कर रह गया है और उसी वर्ग के भीतर मौजूद अति पिछड़ी जातियों को आज भी इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

आरक्षण के इस मुद्दे को गरमाने में न्यायिक फैसलों और टिप्पणियों की भी बड़ी भूमिका रही है। समय-समय पर अदालतों द्वारा दिए गए निर्देशों ने इस बहस को एक नई दिशा दी है। जब भी आरक्षण की सीमा को बढ़ाने या इसके भीतर नए वर्गीकरण की बात उठती है तो कानूनी और संवैधानिक अड़चनें सामने आती हैं। यह द्वंद्व समाज में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। एक तरफ वह वर्ग है जिसे लगता है कि सदियों के वंचन के बाद उसे जो अधिकार मिले हैं वे छीने जा रहे हैं या उन्हें कमजोर किया जा रहा है। दूसरी तरफ वह वर्ग है जो यह मानता है कि लगातार बढ़ते आरक्षण के कारण योग्यता की अनदेखी हो रही है और उनके लिए अवसर कम होते जा रहे हैं। यह वैचारिक टकराव समाज को दो स्पष्ट ध्रुवों में बांटता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में यह मुद्दा सिर्फ सरकारी नौकरियों या शिक्षा में प्रवेश का नहीं रह जाता बल्कि यह सामाजिक अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई बन जाता है।

आज के युवाओं के बीच आरक्षण को लेकर एक अलग ही स्तर की बहस चल रही है। एक तरफ आरक्षित वर्ग के युवा हैं जो मानते हैं कि यह उनके ऐतिहासिक अधिकारों की प्राप्ति का साधन है और सामाजिक संरचना में उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का एकमात्र जरिया है। उनका संघर्ष उन अदृश्य बाधाओं से है जो समाज ने उनके सामने खड़ी की हैं। दूसरी तरफ अनारक्षित वर्ग के युवा हैं जो भारी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जब कोई मेधावी छात्र केवल इसलिए किसी परीक्षा या प्रवेश से वंचित रह जाता है क्योंकि वह एक विशेष वर्ग में पैदा हुआ है तो उसके भीतर पनपने वाली निराशा को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह स्थिति समाज में एक मौन दरार पैदा कर रही है जो अक्सर सोशल मीडिया पर चलने वाले अभियानों और कभी-कभी सड़कों पर होने वाले उग्र प्रदर्शनों के रूप में बाहर आती है। यह टकराव केवल युवाओं की मानसिक शांति को ही भंग नहीं कर रहा है बल्कि यह देश की उस सामूहिक ऊर्जा को भी विभाजित कर रहा है जिसे राष्ट्र निर्माण में लगना चाहिए था।

राजनीतिक दलों के लिए आरक्षण हमेशा से एक मुफीद मुद्दा रहा है। चुनाव चाहे पंचायत के हों या लोकसभा के जातियों का गणित हमेशा अहम भूमिका निभाता है। राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए इस मुद्दे को बहुत सलीके से हवा देती हैं। जब विकास रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर जवाब देना मुश्किल होने लगता है तब आरक्षण और जातीय पहचान जैसे भावनात्मक मुद्दे बहुत काम आते हैं। यह एक ऐसी बिसात है जिस पर हर दल अपनी सुविधा के अनुसार गोटियां बिछाता है। आज हम देख रहे हैं कि जो दल कल तक आरक्षण के किसी विशेष स्वरूप का विरोध करते थे वे आज राजनीतिक मजबूरियों के चलते उसी का समर्थन कर रहे हैं। यह राजनीतिक अवसरवाद इस बात का परिचायक है कि आरक्षण के मुद्दे में कितनी अपार चुनावी संभावनाएं छिपी हैं। इस पूरी प्रक्रिया में मूल समस्या कहीं पीछे छूट जाती है और पूरा जोर सिर्फ तात्कालिक लाभ उठाने पर रहता है।

इस मुद्दे का एक और महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक बनाम सामाजिक पिछड़ेपन की बहस है। एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि आरक्षण का आधार जाति न होकर आर्थिक स्थिति होनी चाहिए क्योंकि गरीबी किसी एक जाति तक सीमित नहीं है। उनका तर्क है कि एक गरीब सवर्ण को भी उसी मदद की जरूरत है जो किसी अन्य वर्ग के गरीब को है। आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण ने इस बहस को और भी जटिल बना दिया है। वहीं सामाजिक न्याय के पैरोकारों का स्पष्ट मत है कि भारतीय समाज में जाति एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। उनका मानना है कि पिछड़ापन केवल पैसे की कमी नहीं है बल्कि यह पीढ़ियों से चले आ रहे सामाजिक बहिष्कार और हीन भावना का परिणाम है जिसे केवल आर्थिक मदद से दूर नहीं किया जा सकता।

संस्थागत नीतियों और निजीकरण के बढ़ते प्रभाव ने भी इस बहस को एक नया आयाम दे दिया है। आज सरकारी क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है और ज्यादातर रोजगार निजी क्षेत्र में पैदा हो रहे हैं। ऐसे में यह सवाल जोर शोर से उठाया जा रहा है कि क्या निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। कुछ संगठन खुले तौर पर इसकी वकालत कर रहे हैं और उनका तर्क है कि जब देश के संसाधन सभी के हैं तो निजी क्षेत्र को भी सामाजिक न्याय के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसके विपरीत उद्योग जगत का मानना है कि निजी क्षेत्र पूरी तरह से योग्यता और दक्षता पर आधारित होता है और वहां आरक्षण लागू करने से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय कंपनियां पिछड़ सकती हैं। यह एक बेहद जटिल प्रश्न है जिस पर आम सहमति बनाना फिलहाल कठिन प्रतीत होता है।

हमें यह भी सोचना होगा कि क्या केवल आरक्षण ही समाज के सभी वर्गों के उत्थान का एकमात्र उपाय है।

जब तक शिक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत और सुलभ नहीं बनाया जाता कि समाज के हाशिए पर खड़ा बच्चा बिना किसी बैसाखी के प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सके तब तक समानता का लक्ष्य अधूरा है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक गुणवत्ता और समान अवसर सुनिश्चित किए बिना आरक्षण का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इसका लाभ वास्तव में उन्हें मिले जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है न कि उन लोगों को जो पहले से ही साधन संपन्न हो चुके हैं। आरक्षण एक औजार है साध्य नहीं और अंतिम लक्ष्य एक समरस और समतामूलक समाज का निर्माण ही होना चाहिए।

नजरिया

राहुल गांधी की माया अपरम्पार

प्रधान के बाद शाह और फिर मोदी का नम्बर

बाल मुकुन्द ओझा

मोबाइल : 9414441218

भाजपा का कहना है जब उनकी पार्टी ही उन्हें गंभीरता से नहीं लेती तो हम क्यों ले। चौकीदार चोर, पनोती और जेब कतरा से लेकर अम्बानी अडानी के मुद्दे फेल हो चुके है। या यों कहे जनता ने नकार दिए। वे मोदी पर निजी हमले करने से बाज नहीं आते मगर जनता की अदालत में हर बार ठुकरा दिए जाते है। राहुल गांधी की एक दशक की सियासी यात्रा पर ष्टिपात करें तो पाएंगे कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने मोदी पर तरह तरह के आरोप लगाए। राहुल के बयानों पर भाजपा आग बबूला हो रही है वहां इंडि गठबंधन की सहयोगी पार्टियां राहुल के बयानों का समर्थन कर अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रही है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गाँधी की माया अपरम्पार है। पहले उन्होंने पेपर लीक का जिम्मेदार मानते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग की और कहा इस्तीफ़ा देने पर ही लोकसभा की कार्यवाही सुचारु रूप से चलेगी। चलो इस्तीफ़ा भी हो गया और उनकी मांग पूरी हो गई। लगा कि अब लोकसभा बिना विघ्न बाधा चलेगी। मगर राहुल अपनी बात पर कायम नहीं रहे और लगे हाथ गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफ़ा मांग डाला। शाह का इस्तीफ़ा नहीं होगा तो उनकी पार्टी लोकसभा नहीं चलने देगी। अब एक बार फिर हम राहुल गाँधी के छिपे एजेंडे का खुलासा करना चाहते है। उनकी मांग पर जो कभी पूरी होने वाली नहीं है, यदि अमित शाह इस्तीफ़ा दे देते है तो उनकी अगली मांग फिर तैयार है। यह मांग होगी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफ़ा दे और वे इस्तीफ़ा नहीं देते है तो राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त करे। यह विचारनीय बात है कि एक चुनी हुई सरकार कांग्रेस नेता के एजेंडे पर चलेगी या अपनी नीतियों और कार्यक्रमों पर। लोकतंत्र छल कपट से चलने वाली चीज़ नहीं है। यदि आप सत्तासीन होना चाहते है तो जनता की अदालत में जाए। जनता यदि आपको चुनती है तो आप देश पर राज करे।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का विवादों से पुराना नाता है। विशेषकर नरेंद्र मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद राहुल गाँधी उनपर तरह तरह के आरोप लगाते रहते है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कई बार विवादित बयान दिये है। इससे पूर्व रायबरेली में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री को गद्दार' कहा था। राहुल गांधी के हालिया बयानों पर एक नज़र डाले तो पता चलेगा, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर सिर चढ़कर बोलने लगा है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता अर्बन नक्सली जैसी है। राहुल पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी परिवारवाद की उपज हैं। उन्होंने देश का अपमान किया है। राहुल गांधी टुकड़े-टुकड़े गैंग के लीडर हैं। राहुल के बयान उनकी मानसिकता को बताते हैं। राहुल ने देश की जनता का अपमान किया है।

नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी के गुस्से में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वे अपने गुस्से का इजहार करने के दौरान जो बातें कह रहे है वे लोगों को हज़म नहीं हो रही है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गाँधी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने का कोई भी मौका छोड़ नहीं रहे है। राहुल गाँधी मोदी के बहाने बेसिरपैर के आरोप लगाते तनिक भी नहीं हिचकिचाते। मगर वे यह भूल गए देश की जनता ने नेहरू, इंदिरा और राजीव की भांति मोदी को भी प्रचंड बहुमत के साथ देश का ताज पहनाया है।

राहुल गांधी को लोग गंभीरता से क्यों नहीं लेते है, यह प्रश्न सियासी क्षेत्रों में तेजी से चर्चित हो रहा है। राहुल गांधी को बहुत गुस्सा आता है जब लोग उन्हें तरह तरह की उपमाओं से नवाजते है। राहुल ने अपने विवादित बयानों से कई बार मोदी को पटकने की चेष्टा की मगर हर बार उनका दांव खाली गया। चौकीदार चोर से लेकर आरक्षण ख़त्म करने के उनके बयान हवा हवाई साबित हुए। भाजपा का कहना है जब उनकी पार्टी ही उन्हें गंभीरता से नहीं लेती तो हम क्यों ले। चौकीदार चोर, पनोती और जेब कतरा से लेकर अम्बानी अडानी के मुद्दे फेल हो चुके है। या यों कहे जनता ने नकार दिए। वे मोदी पर निजी हमले करने से बाज नहीं आते मगर जनता की अदालत में हर बार ठुकरा दिए जाते है। राहुल गांधी की एक दशक की सियासी यात्रा पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने मोदी पर तरह तरह के आरोप लगाए। राहुल के बयानों पर भाजपा आग बबूला हो रही है वहां इंडि गठबंधन की सहयोगी पार्टियां राहुल के बयानों का समर्थन कर अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रही है। राहुल को अपने आरोपों के समर्थन में अपने देश में ही सशक्त आंदोलन कर जनता का समर्थन जुटाना चाहिए मगर चीन जैसे दुश्मन देश के पक्ष में बोलकर देशवासियों की सहानुभूति खो रहे है। गौरतलब है राहुल ने देश की सवैंधानिक संस्थाओं यथा चुनाव आयोग, न्यायालय और प्रेस पर भी समय समय पर हमला बोला है।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टेंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

भारी बारिश

असम के गुवाहाटी में बृहस्पतिवार को भारी बारिश के बाद जलमग्न हुई सड़क से गुजरते राहगीर।

शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त चश्मा पहनने पर ट्रोल हुईं भूमि पेडनेकर

मुंबई/एजेन्सी

एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर पूजा करते हुए एक वीडियो शेयर करने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही हैं। 'दम लगा के हईशा' से बॉलीवुड करियर शुरू करने वाली अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने 'बाला', 'शुभ मंगल सावधान' और 'भुज' जैसी फिल्मों में अपने काम से दर्शकों का दिल जीता। पर्दे पर वो अक्सर मजबूत किरदारों में दिखती हैं। सोशल मीडिया पर भी वह अपनी लाइफ के छोटे-बड़े पल फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। चाहे जिम की वीडियो हो या फैमिली के साथ तस्वीरें, भूमि हर चीज खुलकर पोस्ट करती हैं। भूमि पेडनेकर ने इंस्टाग्राम पर भगवान शिव की पूजा की कुछ तस्वीरें और एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में भूमि शिवलिंग पर जल चढ़ाती हुई दिखाई दे रही थीं। उन्होंने इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, 'जैसे ही सावन शुरू होता है, मैं आसान जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि

इसे शान से जीने की ताकत के लिए प्रार्थना करता हूं। हर हर महादेव।'भूमि का ये पोस्ट देखकर कई फैंस ने कमेंट में 'हर हर महादेव' लिखा और उनकी भक्ति की तारीफ भी की, लेकिन इसी पोस्ट के साथ कुछ चीजें ऐसी थीं, जिन पर लोगों की नजर पड़ी और देखते ही देखते वह ट्रोल होने लगीं। दरअसल, वीडियो और फोटो में भूमि ने ब्लैक कलर का सिंपल टॉप और ब्लू डेनिम जींस पहनी हुई थी। सबसे बड़ी बात, इस दौरान उन्होंने सनग्लासेस पहन रखा था। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय भी उन्होंने आंखों पर चश्मा लगाया हुआ है।आंखों पर चश्मे को देख लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि पूजा के समय सादगी और मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए।इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कई कमेंट्स किए। एक यूजर ने लिखा, ''क्या जरूरत है ऐसे चश्मा लगा के पूजा करने की? हद है।''दूसरे यूजर ने कहा, ''महादेव की पूजा कम और फोटो शूट ज्यादा लग रहा है, प्लीज ऐसी चीजें पोस्ट मत करो।'अन्य यूजर्स ने लिखा, 'मंदिर में भगवान की भक्ति कर रही हों आप या फिर फोटोशूट।'कुछ यूजर्स ने तंज कसते हुए लिखा, ''इन्हें पूजा में भी फैशन और स्टाइल चाहिए... वरना आम नागरिक लगने लगेंगी पूजा करते हुए।'एक अन्य यूजर ने कमेंट में लिखा, 'चश्मा तो उतार लेती मैडम जी। अगर दिल से पूजा करनी है तो कैमरे और स्टाइल की जरूरत नहीं है।''एक और यूजर ने कहा, ''सेलेब्स हर चीज को कंटेंट बना देते हैं, चाहे वो भक्ति ही क्यों न हो।'' हालांकि भूमि के कुछ फैंस उनके सपोर्ट में भी उतरे। उन्होंने कहा, ''भक्ति दिल से होती है। भगवान चश्मे या कपड़े नहीं देखते। अगर कोई सच्चे मन से पूजा कर रहा है तो उसे जज नहीं करना चाहिए।'

मुंबई में 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के विशेष प्रीमियर के दौरान पोज देते इन्फ्लुएंसर आवेज़ दरबार और अभिनेत्री कुब्रा सैत।

भुगतान एवं शुल्क विवाद: 15 अगस्त से स्विगी की सेवाएं बंद कर सकते हैं बेंगलूरु के होटल

बेंगलूरु। बेंगलूरु होटल्स एसोसिएशन (बीएचए) ने चेतावनी दी है कि ऑनलाइन खाद्य आपूर्ति मंच स्विगी के भुगतान में पारदर्शिता, अनधिकृत कटौतियों और विज्ञापन शुल्क से जुड़े लंबित मुद्दों का समाधान नहीं करने पर उससे संबद्ध होटल तथा शहर के अन्य आतिथ्य संगठनों से जुड़े प्रतिष्ठान 15 अगस्त से उसके साथ कारोबार बंद कर देंगे। एसोसिएशन ने कहा कि उसने स्विगी को इन मुद्दों का बातचीत के जरिये निपटान करने का अंतिम अवसर दिया है लेकिन यदि सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो स्वतंत्रता दिवस से उससे संबद्ध सभी संगठन मंच के साथ कारोबार बंद कर देंगे।

एसोसिएशन ने बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ऐसा नहीं होने पर बेंगलूरु में हमारे सभी संबद्ध संगठनों ने सर्वसम्मति से 15 अगस्त से स्विगी के साथ सभी तरह का कारोबार निलंबित करने का फैसला किया है। एसोसिएशन का आरोप है कि स्विगी होटल मालिकों की लिखित या डिजिटल सहमति लिए बिना सीपीसी, सीपीए या प्रायोजित विज्ञापन शुरू करने से पहले ही विज्ञापन तथा प्रचार शुल्क काट रही है।

डिजिटल मार्केटिंग में सीपीसी और सीपीए ऑनलाइन विज्ञापन के दो सबसे महत्वपूर्ण मूल्य निर्धारण मॉडल हैं। बीएचए के मानद अध्यक्ष पी. सी. राव ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि मुख्य समस्या मंच की भुगतान प्रणाली है। उन्होंने कहा, मुख्य समस्या यह है कि भुगतान एवं 'पेआउट' (भुगतान वितरण) प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है। इसमें बहुत अधिक कटौतियां की जा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसोसिएशन को स्विगी के सेवा शुल्क पर कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि अतिरिक्त कटौतियों पर आपत्ति है।

डूरंड कप : एफसी रेंगदाई और समलेश्वरी स्पोर्टिंग जीते

इंफाल/.भाषा। एफसी रेंगदाई ने बृहस्पतिवार को यहां अपने पहले ही डूरंड कप मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए पिछले चरण के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली इंडियन नेवी फुटबॉल टीम को ग्रुप डी मुकाबले में 1-0 से हरा दिया। एफसी रेंगदाई की ओर से स्थानापन्न खिलाड़ी खैदेम अमरजीत सिंह ने 58वें मिनट में निर्णायक गोल दागा। यह डूरंड कप में एफसी रेंगदाई का पहला गोल भी था और इसी के दम पर टीम ने यादगार जीत दर्ज की। वहीं कोलकाता में हुए एक अन्य मैच में समलेश्वरी स्पोर्टिंग ने बागपत एफसी को 4-1 से हराकर अगले दौर में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार रखीं।

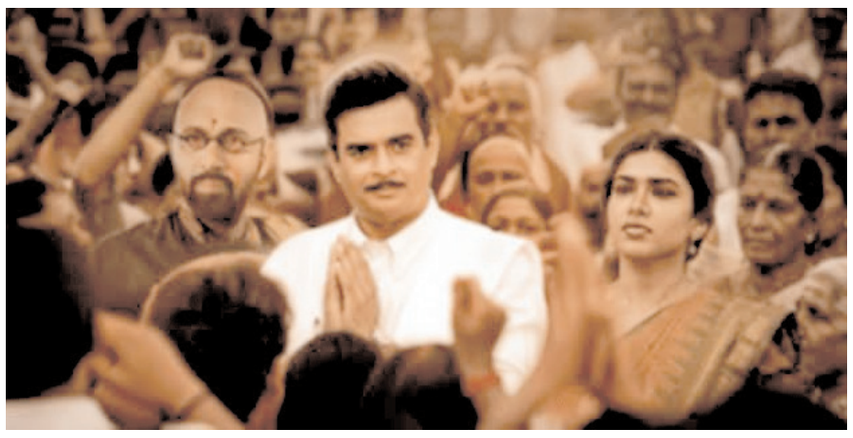

अभिनेत्री अदिति बालन की फिल्म 'जीडीएन' से पहला लुक जारी

मुंबई/एजेन्सी

निर्देशक कृष्ण कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जीडीएन' सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार है। इसी बीच, मेकर्स ने गुरुवार को अभिनेत्री अदिति बालन का लुक भी जारी किया। मेकर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभिनेत्री का पहला लुक जारी कर लिखा, पेश है, पद्मावती के रूप में अदिति बालन। एक आवाज, स्टैंड और ऐसी कहानी, जो सब कुछ बदल देती है। यह फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार हैं। यह फिल्म मशहूर भारतीय आविष्कारक, किसान और समाजसेवी जी.डी. नायडू के जीवन पर आधारित है, जिसमें अभिनेत्री अदिति बालन पद्मावती की भूमिका अदा करती हुई सभी को मनोरंजन करेंगी।मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज कर दिया है, जिसमें महान आविष्कारक गोपालस्वामी दोरैस्वामी नायडू (जीडी नायडू) के जीवन, संघर्ष और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनकी असंदिग्ध बगावत की एक रोमांचक झलक दिखाता है। इसकी शूटिंग मुख्य रूप से कोयंबटूर में की गई है, जहां नायडू ने अपनी कर्मभूमि बनाई थी।ट्रेलर की शुरुआत स्वतंत्रता-पूर्व काल के उन चुनौतीपूर्ण दौर से होती है, जहां 'भारत के एडिसन' कहे जाने वाले जीडी नायडू के अपरंपरागत विचारों और आविष्कारों को सत्ताधारी ब्रिटिश हुकूमत और ताकतवर ताकतों द्वारा दबाने की कोशिश की जाती है। इसके बाद एक ब्रिटिश अधिकारियों को यह कहते हुए दिखाया गया है कि नायडू नाजियों और जर्मनी के साथ व्यापार कर रहे हैं, जो क्राउन के खिलाफ यानी राजद्रोह है। उन पर कर चोरी और अन्य मनगढ़ंत आरोप भी लगाए जाते हैं।कृष्णकुमार रामकुमार द्वारा निर्देशित 'जीडीएन' में आर. माधवन मुख्य भूमिका में हैं, जिन्हें 'भारत का एडिसन' कहे जाने वाले जी.डी. नायडू के रूप में देखा जा सकता है। फिल्म में माधवन के अलावा जयराम, प्रियामणि, दुशारा विजयन, सत्यराज, अदिति बालन, विजय राय और टीजे अरुणासलम भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत गोविंद वसंत ने दिया है और सिनेमैटोग्राफी अरविंद कमलानाथन ने की है। यह फिल्म 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि फिल्म को दर्शक किस कदर प्यार देते हैं।

रामायण: पार्ट 1' का ट्रेलर ब्रह्ममुहूर्त में पांच भाषाओं में रिलीज हुआ

मुंबई/एजेन्सी

निर्देशक नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित पौराणिक गाथा 'रामायण: पार्ट 1' का आधिकारिक ट्रेलर गुरुवार ब्रह्ममुहूर्त में हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम सहित पांच भारतीय भाषाओं में रिलीज किया गया। 4 मिनट 9 सेकंड का ट्रेलर काफी शानदार है। इसकी शुरुआत यश के रावण रूप में लंका की राज गद्दी संभालने से होती है। इसके बाद ट्रेलर रामायण की पौराणिक कथा को आगे बढ़ाता है, जिसकी शुरुआत अयोध्या में भगवान राम की उपस्थिति से होती है। ट्रेलर में रामायण की अहम घटनाओं की झलक दिखाई गई है। इसमें प्रभु राम के वनवास से पहले ही घटनाओं को दिखाया गया है, जिसमें माता कैकयी राम के वनवास की मांग रखती है। अपनी माता की मांग का सम्मान करते हुए प्रभु राम वनवास को निकलते हैं, जिसके बाद शूर्पणखा प्रसंग और 'सीता हरण' तक, ट्रेलर इस महाकाव्य की प्रमुख घटनाओं की विस्तृत झलक पेश करता है।महाकाव्य रामायण की कास्ट काफी दमदार नजर आ रही है। इसमें रणबीर कपूर भगवान राम

के रूप में, साई पल्लवी माता सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आ रहे हैं। लारा दत्ता कैकेयी की भूमिका में है, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के रूप में और अरविंद गोविल राजा दशरथ के रूप में नजर आ रहे हैं।

ट्रेलर देखकर लग रहा है कि इन सभी कलाकारों ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है।नितेश तिवारी की फिल्म का लेखन अवॉर्ड विनिंग लेखक श्रीधर राघवन ने किया है, जबकि इसका संगीत म्यूजिक ऑस्कर विनर हंस जिमर और ए.आर. रहमान ने मिलकर बनाया है। इस फिल्म में कई क्षेत्रों के कलाकारों का अब तक का सबसे बड़ा साथ देखने को मिलेगा।फिल्म के एक्शन दृश्यों की जिम्मेदारी टेरी नोटरी और गाय नॉरिस संभाल रहे हैं, जबकि प्रोडक्शन डिजाइन की जिम्मेदारी रैम्से एवरी और रवि बंसल ने संभाली है। इसके अलावा दुनिया भर के हजारों कलाकार, डिजाइनर और तकनीकी विशेषज्ञ भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। एक्शन-एडवेंचर प्रोजेक्ट फिल्म 'रामायण' का वैश्विक वितरण सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट करेगी।

यूजर्स की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं : मेटा ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय से कहा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नैनीताल/भाषा। मेटा ने बृहस्पतिवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय को बताया कि उसने अपनी शिकायत निवारण नीति में बदलाव किया है और अब यूजर्स की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है।मेटा का यह स्पष्टीकरण फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने, आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने, ऑनलाइन उगाही के प्रयासों तथा यूजर्स की शिकायतों पर सोशल मीडिया मंचों द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं किए जाने से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया।सुनवाई के दौरान मेटा की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि कंपनी ने अपनी शिकायत निवारण नीति में संशोधन किया है और अब यूजर्स की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से सोशल मीडिया मंचों की कार्यप्रणाली में मौजूद कमियों तथा उन्हें दूर करने के सुझाव अदालत के समक्ष रखने को कहा, ताकि ऐसी घटनाओं पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जा सके। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की है। अधिवक्ता आलोक कुमार ने वर्ष 2021 में यह जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि अज्ञात लोगों ने उनके नाम से फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाई, उस पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किए और उनसे धन उगाही का प्रयास किया। याचिका में कहा गया कि शिकायत किए जाने के बावजूद फेसबुक ने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण उन्हें अपने मित्रों और परिजनों के सामने अपमान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।

याचिका में सभी सोशल मीडिया मंचों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे यूजर्स की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा फर्जी अकाउंट बनाने और ऑनलाइन उगाही में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं, ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

अच्छे किरदार मिलना मेरी किस्मत का हिस्सा है : शहनाज गिल

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री शहनाज गिल ने अपने करियर में एक लंबा सफर तय किया है। कभी अपनी चुलबुली अदाओं और बेफिक्र अंदाज से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही। इन दिनों वह हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'इश्कनामा' को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म में वह एक गंभीर भूमिका में नजर आ रही है। पर्दे पर निभाए गए किरदारों को लेकर शहनाज ने कहा कि यह सब उनके सफर और किस्मत का हिस्सा है। जब आईएएनएस ने शहनाज गिल से पूछा कि क्या वह दर्शकों को अपने व्यक्तित्व का दूसरा पहलू दिखाने या अपनी पुरानी छवि बदलने के लिए इस तरह के किरदार चुन रही हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि उनका ऐसा कोई मकसद नहीं है। शहनाज ने कहा, मैं कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रही हूं। मेरी किस्मत इसे साबित कर रही है। भगवान मुझे ताकत दे रहे हैं। उनकी कृपा से मुझे अच्छी स्क्रिप्ट मिल रही हैं। जो भी मुझे मौके मिल रहे हैं, उन्हें मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाने की कोशिश कर रही हूं। एक कलाकार का सफर लगातार सीखने और खुद को बेहतर करने का होता है। मैं किसी एक छवि में बंधकर काम नहीं करना चाहतीं, बल्कि अलग-अलग तरह की कहानियों का हिस्सा बनना चाहती हैं।'' बातचीत में शहनाज से पूछा गया कि अगर उनकी जिंदगी की अपनी कोई 'इश्कनामा' यानी प्रेम कहानी हो, तो उसका टाइटल क्या होगा। इस सवाल पर अभिनेत्री ने कहा, जब मेरी जिंदगी पर फिल्म बनेगी तो मुझे लगता है कि वह बहुत दिलचस्प होगी, और जब ऐसा होगा, तब मैं उसका टाइटल भी बताऊंगी। फिल्म में अपने किरदार को लेकर शहनाज गिल ने कहा, ''मुझे लगता है कि जब किसी सच्ची कहानी पर फिल्म बनाई जाती है तो जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी होता है। मैंने अपनी तरफ से इस जिम्मेदारी को पूरी क्षमता के साथ निभाने की कोशिश की है। मुझे विश्वास है कि मेरे किरदार को लोग जरूर पसंद करेंगे।'' बता दें कि 'इश्कनामा' एक सच्ची कहानी पर आधारित है। फिल्म में भारत-पाकिस्तान सीमा की पृष्ठभूमि के बीच प्यार और रिश्तों की कहानी दिखाई गई है। यह फिल्म साल 1981 से 1988 के बीच की घटनाओं पर आधारित है, जिसमें निर्मल निम्मा और नसीमा की प्रेम कहानी को दिखाया गया है। 'इश्कनामा' का निर्देशन अरविंद्र एस. खैरा ने किया है, जबकि फिल्म का निर्माण सौरभ राणा और रवनीत कौर चहल ने किया है। यह फिल्म किताब 'हिंद पाक बॉर्डरनामा' से प्रेरित बताई जा रही है।

सिर्फ स्क्रीन पर दिखना नहीं, असर छोड़ने वाले किरदार निभाना चाहती हूं : बरखा सिंह

मुंबई/एजेन्सी

मुंबई बरखा सिंह ने अपने करियर की शुरुआत हल्के-फुल्के रोमांटिक और कमिंग-ऑफ-एज किरदारों से की थी, लेकिन पिछले तीन सालों में उन्होंने अपनी अभिनय यात्रा को एक नया आयाम दिया है। क्रिमिनल जस्टिस और अब टैक्स डिपार्टमेंट स्टोरी जैसे प्रोजेक्ट्स में दमदार और चुनौतीपूर्ण किरदार निभाकर उन्होंने खुद को एक बहुमुखी अभिनेत्री के रूप में साबित किया है। बरखा का मानना है कि वह ऐसे किरदार निभाना चाहती हैं जो सिर्फ कहानी का हिस्सा न हों, बल्कि दर्शकों पर गहरी छाप भी छोड़ें।टैक्स डिपार्टमेंट स्टोरी में वह पहली बार एक भारतीय राजस्व सेवा (खठड) अधिकारी के दमदार किरदार में नजर आएंगी। अपने बदलते करियर चुनावों पर बात करते हुए बरखा ने कहा कि टैक्स डिपार्टमेंट स्टोरी में खठड अधिकारी का किरदार निभाना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा और इससे उन्हें यह और भी स्पष्ट हो गया कि आगे वह किस तरह के किरदार करना चाहती हैं।

बरखा सिंह ने कहा, मैं टैक्स डिपार्टमेंट स्टोरी में खठड अधिकारी

का किरदार निभाने को लेकर बेहद उत्साहित हूं। मेरी कोशिश हमेशा ऐसे किरदार निभाने की रहती है जो कहानी में सिर्फ मौजूद न हों, बल्कि उसे आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएं।

मुझे ऐसे किरदार पसंद हैं जिनकी अपनी मजबूत आवाज़ हो, जो आज के दौर की जटिलताओं को दिखाएं और दर्शकों को कुछ सोचने पर मजबूर करें। अपनी विशलिस्ट के फिल्ममेकर्स का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, अगर मेरी विशलिस्ट की बात करूं तो लापता लेडीज़ के बाद मैं किरण राव के साथ काम करना चाहूंगी। इसके अलावा राख जैसी शानदार स्टोरीटेलिंग के लिए प्रोसित रॉय और पाताल लोक में बेहतरीन काम करने वाले अविनाश अरुण के साथ काम करना भी मेरा सपना है। इन तीनों की कहानी कहने की शैली बेहद अलग और प्रेरणादायक है। बरखा सिंह जल्द ही टैक्स डिपार्टमेंट स्टोरी में एक बिल्कुल नए और दमदार अंदाज़ में खठड अधिकारी की भूमिका निभाती नजर आएंगी। दिलचस्प प्रोजेक्ट्स और स्पष्ट रचनात्मक सोच के साथ बरखा लगातार ऐसे किरदार चुन रही हैं जो न सिर्फ उनकी अभिनय क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ें।

विफा पांडिचेरी चैप्टर की कार्यकारिणी का पुनर्गठन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पांडीचेरी। विप्र फाउंडेशन पांडिचेरी चैप्टर एवं जोन 17-बी तमिलनाडु की बैठक पांडिचेरी में किशोर सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जोन अध्यक्ष ने संगठन का महत्व बताते हुए कहा कि हम सब को मिलकर जोन को मजबूत बनाना है। उन्होंने दक्षिण क्षेत्रीय महामंत्री भगवान व्यास से अनुरोध किया कि राष्ट्रीय परिषद द्वारा लिए गए निर्णय और संगठन के बारे में बताएं। भगवान व्यास ने विप्र फाउंडेशन द्वारा किए गए कार्यों एवं नीतियों की जानकारी सदस्यों को दी। उन्होंने विप्र फाउंडेशन के प्रकल्पों एवं संगठनात्मक निर्णयों की भी विस्तृत जानकारी दी। बैठक में सर्वसम्मिति से पांडिचेरी चेप्टर की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसमें अध्यक्ष देवीलाल राजपुरोहित, सचिव ब्रह्मानंद पारीक, कोषाध्यक्ष गोपाल राजपुरोहित, उपाध्यक्ष दयाराम राजपुरोहित व सुभाष दाधीच, सहमंत्री सुरेश पारीक व नरपत सिंह राजपुरोहित को मनोनीत किया गया। कार्यकारणी समिति में कमल किशोर दाधीच, अमृत सिंह राजपुरोहित, चेतन शर्मा, दिलीप सिंह राजपुरोहित, नरपत सिंह राजपुरोहित, राम सिंह राजपुरोहित को शामिल किया गया।महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष चंदा शर्मा, मंत्री अनीता पारीक, कोषाध्यक्ष दुर्गा कंवर राजपुरोहित, परसदेवी को सर्वसम्मिति से चुना गया। पूर्व अध्यक्ष एवं मनोनीत पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। चैप्टर के मंत्री के धन्यवाद प्रस्ताव के बाद बैठक सम्पन्न हुई।

किसी भी समस्या का समाधान भागने से नहीं बल्कि जागने से मिलता है : कपिल मुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहाँ चूलै में मणिक्कम स्ट्रीट स्थित लक्ष्मी महल में चातुर्मासार्थ विराजित क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री कपिल मुनि जी ने गुरुवार को प्रवचन के दौरान कहा कि जीवन का शाश्वत सत्य है। संसार में जिसने भी कुछ पाया है उसने पहले स्वयं को जगाया है। और जो सोया रहा चाहे वह नींद शरीर की हो या चेतना की वह जीवन के अमूल्य अवसर खोता चला गया। जीवन में कुछ भी उपलब्ध करने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है जागना। बिना जागरण के न ज्ञान मिलता है, न सफलता, न शांति और न ही आत्मकल्याण। जो जाग गया उसके लिए हर समस्या एक अवसर बन जाती है जो सोया रहा उसके लिए हर अवसर भी समस्या बन जाता है। मनुष्य प्रायः कठिनाइयों से घबराकर भागना चाहता है। वह परिस्थितियाँ बदलना चाहता है, स्थान बदलना चाहता है, लोगों को बदलना चाहता है किंतु स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं करता। सत्य यह है कि किसी भी समस्या का समाधान भागने से नहीं, बल्कि जागने से मिलता है। अंधकार से लड़ने की आवश्यकता नहीं होती, केवल दीपक जलाना होता है। उसी प्रकार अज्ञान से संघर्ष करने की अपेक्षा चेतना को जागृत करना आवश्यक है। आज का मनुष्य तन के स्तर पर जाग रहा है। स्वास्थ्य के प्रति सजग है। धन के स्तर पर जाग रहा है। व्यवसाय और संपत्ति बढ़ाने में दिन-रात लगा हुआ है। परिवार के स्तर पर भी जाग रहा है। यहाँ जागरण का अर्थ आँखें खुली रखना नहीं, बल्कि चेतना का जागना है। स्वयं को पहचानना, जीवन के उद्देश्य को समझना और सत्य की ओर अग्रसर होना ही वास्तविक जागरण है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसके पास साधन कम हैं सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह भ्रम में जी रहा है।

वह अस्थायी को स्थायी समझ बैठा है, साधन को साध्य मान बैठा है और शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठा है। जब तक यह भ्रम बना रहता है, तब तक सत्य का दर्शन नहीं होता। भ्रम के टूटने पर ही वास्तविकता का बोध होता है। लोकमत हमेशा सत्य का पर्याय नहीं होता। भीड़ की अपनी कोई दिशा नहीं होती। वह स्वयं नहीं सोचती केवल अनुसरण करती है। भीड़ का कोई नीड़ नहीं होता। जो भीड़ के साथ बहता है वह अपनी मौलिकता खो देता है और जो सत्य के साथ चलता है वही इतिहास रचता है। सभा का संचालन मंत्री शांतिलाल गुगलिया ने किया।

पाँच दिवसीय नि:शुल्क एक्यूप्रेशर स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न

बेंगलूरु/दक्षिण भारत । बेंगलूरु जैन सेवा मंडल द्वारा खागा कार्यालय में पाँच दिवसीय नि:शुल्क एक्यूप्रेशर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसमें थेरेपिस्ट रूपेश कुमार एवं उनकी विशेषज्ञ चिकित्सक टीम ने 200 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक परामर्श दिया। मंडल के अध्यक्ष वसंत जैन, उपाध्यक्ष दिलीप जैन, सचिव कीर्तिकुमार बंदामुथा आदि ने शिविर में सहयोग किया।

इस मौके पर एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ मुकेश जाखड़ ने सेमीनार का आयोजन किया। समापन के मौके पर पूरी चिकित्सीय टीम का सम्मान किया गया।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

गुरु इकतीसा पाठ

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अखिल भारतीय ख़तरगच्छ युवा परिषद द्वारा बेंगलूरु के बसवनगुड़ी स्थित विमलनाथ जैन मंदिर एवं दादावाड़ी में श्रद्धा एवं भक्ति के साथ दादा गुरुदेव का इकतीसा पाठ आयोजित किया गया। गायक अरविन्द चोपड़ा एवं जीतू झाबक ने भजनों की प्रस्तुति दी। मुनिश्री मलयप्रभजी व साध्वीश्री प्रियश्रद्धांजनाश्रीजी से श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

क्रोध की रणभूमि नहीं, तप- साधना की तपोभूमि बनाएं जीवन को : आचार्य कुलबोधिसूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई । शहर के वेपेरी श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन संघ में चातुर्मासार्थ विराजित आचार्यश्री कुलबोधिसूरीश्वरजी ने गौतम किरण परिसर में गुरुवार को आयोजित प्रवचन में मनुष्य जीवन की दुर्लभता और उसके सदुपयोग का प्रेरक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन ही एक ऐसी उपजाऊ भूमि है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी त्रिरत्न की फसल बोई जा सकती है। आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को क्रोध, कपट और दुर्गुणों की रणभूमि न बनाकर तप, नम्रता और संतोष की तपोभूमि बनाएं।

आचार्यश्री ने चार गतियों, देव भूमि, नरक भूमि, तिर्यंच भूमि और मनुष्य भूमि की विवेचना करते हुए कहा कि देव भूमि संगमरमर जैसी है, जहां उपजाऊ भूमि नहीं है। नरक भूमि अग्नि से जली और उखड़ी हुई भूमि है, जबकि तिर्यंच भूमि में भी कुछ बोना संभव नहीं। एकमात्र मनुष्य भूमि ही ऐसी है, जो उपजाऊ है और जहां आत्मकल्याण की फसल उगाई जा सकती है। आचार्यश्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि राई के दाने से यदि शरीर से भूत निकल जाए, लेकिन वही भूत राई के दाने में प्रवेश कर जाए तो उसे निकालना कठिन होगा। इसी प्रकार क्रोध जब भीतर प्रवेश कर जाता है, तो वह व्यक्ति के जीवन और संबंधों को प्रभावित करता है।

आचार्यश्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब वे आहार ग्रहण करने श्रावक के घर जाते थे, तब उन्हें प्रवचन के लिए कई विषय मिल जाते थे। कहीं बाप-बेटे में झगड़ा, कहीं पति-पत्नी में मनमुटाव। उन्होंने कहा कि घर में शांति से जीना है तो दोनों में से किसी एक को नरम होना पड़ेगा। चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा सास गरम, बहू नरम तो घर में शरम; सास भी गरम, बहू भी गरम तो फूटे घर के करम। उन्होंने कहा कि कपड़े का मैल धोया जा सकता है, लेकिन मन के मैल को धोना कठिन है। साधु और धोबी के दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने समझाया कि गुस्सा साधु को भी धोबी बना देता है।दोहरे चरित्र से बाहर निकलें रंगभूमि की चर्चा करते हुए आचार्यश्री ने कहा कि रंगमंच पर कलाकार का व्यक्तित्व और व्यवहार जैसा दिखाई देता है, निजी जीवन में आवश्यक नहीं कि वह वैसा ही हो। इसी प्रकार यह संसार भी एक रंगमंच है, जहां मनुष्य कई बार दोहरा जीवन जीता है। जीवन के बाहरी और भीतरी दोनों पक्षों को सुधारना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए खर्च कर प्रतिष्ठा करवाने वाले व्यक्ति के घर में यदि उपकारी माता-पिता का सम्मान नहीं है, वैयावच्च करने वाले व्यक्ति अपने नौकर के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो यह संसार के दोहरे चरित्र का उदाहरण है। उन्होंने घड़ी का उदाहरण देते हुए कहा कि केवल डायल सुंदर होना पर्याप्त नहीं, उसके भीतर की मशीन भी ठीक होनी चाहिए। इसी प्रकार बाहरी व्यक्तित्व के साथ भीतर के भावों को भी सुधारना होगा। उन्होंने कहा कि दुर्गुणी को सुधारना आसान है, लेकिन मायावी और कपटी व्यक्ति को सुधारना कठिन है। आचार्यश्री ने बताया कि शुक्रवार से शांत सुधारस' ग्रंथ के आधार पर प्रवचन श्रृंखला का शुभारंभ होगा।

अच्छी शिक्षा के बिना चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता : मुनिश्री जयतिलक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। शहर के एसएस जैन संघ साहुकारपेट के जैन भवन में विराजित आचार्य जयमलजी के शिष्य आचार्य जयतिलक मुनिजी ने अपने प्रवचन में श्रद्धालुओं को धर्म, संस्कार, शिक्षा एवं पारिवारिक मूल्यों पर आधारित प्रेरणादायी संदेश प्रदान किया। अपने प्रवचन में गुरुदेव ने कहा कि जीवन का मूल आधार धर्म है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में शांति, सफलता और आत्मिक उन्नति चाहता है तो उसे धर्म को अपनाना चाहिए। धर्म केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जीवन जीने की एक श्रेष्ठ कला है, जो व्यक्ति को सही दिशा प्रदान करती है। मुनिश्री ने माता-पिता और बच्चों के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के समय में अभिभावक बच्चों की पढ़ाई और कैरियर पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन उनके संस्कारों के निर्माण पर अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाते। उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ-साथ उत्तम संस्कार देना भी उतना ही आवश्यक है। संस्कारयुक्त शिक्षा ही व्यक्ति को समाज का आदर्श नागरिक बनाती है।

उन्होंने कहा कि बच्चों को मोबाइल, टीवी और अन्य व्यसनों से दूर रखते हुए नियमित अध्ययन, अनुशासन और परिवार के साथ समय बिताने की प्रेरणा देनी चाहिए। केवल अंक प्राप्त करना ही जीवन की सफलता नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संतश्री ने परिवार की भूमिका पर बल देते हुए कहा कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में माता-पिता, शिक्षक और समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि परिवार में अच्छे संस्कारों का वातावरण होगा तो बच्चे भी उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि माता-पिता स्वयं आदर्श जीवन जिएँ, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी संगति व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाती है, जबकि बुरी संगति जीवन को पतन की ओर धकेल सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे मित्रों और सकारात्मक वातावरण का चयन करना चाहिए।

अंत में मुनिश्री ने सभी श्रद्धालुओं से धर्म, संयम, सदाचार एवं मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को धारण कर ले तो परिवार, समाज और राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल बन सकता है। संघ उपाध्यक्ष सज्जनराज सुराणा ने सभा का संचालन किया।संघ अध्यक्ष डा. संजय पिंचा ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी।

जीतो मैसूरु लेडीज विंग को राष्ट्रीय स्तर पर मिले सात सम्मान

मैसूरु/दक्षिण भारत। जैन इन्टरनेशनल ट्रेड आर्गेनाइजेशन (जीतो) द्वारा समीक्षा-2026 का आयोजन हरिद्वार में किया गया जिसमें विभिन्न चैप्टरों के कार्यों की समीक्षा की गई तथा पुरस्कार दिए गए। इसी श्रृंखला में जीतो मैसूरु चैप्टर लेडीज विंग ने राष्ट्रीय स्तर पर सात प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त कर चैप्टर का गौरव बढ़ाया। जीतो मैसूरु को उड़ान-सक्षम वर्टिकल के लिए सर्वश्रेष्ठ विजेता पुरस्कार, जे पॉइंट एवं जीफ वर्टिकल के लिए प्रशंसा पुरस्कार, आत्मनिर्भर वर्टिकल स्वास्थ्य एवं पोषण वर्टिकल के लिए प्रशंसा पुरस्कार व राष्ट्रीय कॉनक्लेव के लिए प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त हुआ। नॉन मेट्रो शहर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ चैप्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जीतो के अध्यक्ष विनोद बाकलीवाल, सचिव गौतम सालेचा सहित अनेक पदाधिकारियों व सदस्यों ने महिला विंग को शुभकामनाएं दी। मैसूरु महिला विंग की चेयरपर्सन मोना भटेवरा एवं महामंत्री रजनी डागलिया ने इस उपलब्धि को पूरी टीम का प्रयास बताया तथा सभी को धन्यवाद दिया।

आईओबी को मिला वर्ष 2026 का कंज्यूमर फर्स्ट रिजोल्यूशन अवार्ड

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई । इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) को उपभोक्ता विवाद श्रेणी में ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए ट्रांसयूनियन सीआईबीएल द्वारा चेन्नई मे आयोजित एक कार्यक्रम में कंज्यूमर फर्स्ट रिजोल्यूशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अभूतपूर्व सौ प्रतिशत शिकायत समाधान दर हासिल करके यह स्थान सुरक्षित किया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के प्रभावी निवारण में बैंक द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की भी सराहना की है। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक स्कोर के आधार पर, बैंक को अप्रैल 2026 और जून 2026 के महीने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है। ट्रांसयूनियन सीआईबीएल से कस्टमर फर्स्ट रिजॉल्यूशन अवार्ड 2026 शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक स्कोर के आधार पर अप्रैल 2026 और जून 2026 के महीने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में प्रथम श्रेणी में प्रशंसा प्राप्त करने वाला बैंक बन गया है जो बैंक द्वारा मूल्यवान ग्राहकों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों को संबोधित करने और बेहतर ग्राहक सेवा मानकों को प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पुरस्कार ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, उत्कृष्ट सेवा और आरबीआई द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ग्राहकों की शिकायतों के प्रभावी समाधान के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को मान्यता देते हैं।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत आमंत्रण

कोयम्बटूर के शारदा हिंदू विद्यालय के प्रबंधकों ने आगामी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्धमान जैन सेवा संघ(कोयंबटूर)के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को 80वें स्वाधीनता दिवस पर निमंत्रण देते हुए विद्यालय के लिए सहायता के लिए ज्ञापन भी सौंपा। विद्यालय की प्राचार्या सेलीन सिसिलिया ने सेवा संघ के संस्थापक राजेश कुमार गादिया एवं स्मेश चोरड़िया को कार्यक्रम में आमंत्रित किया तथा शैक्षणिक सहायता माँग पत्र भी दिया।

सुपार्श्वनाथ युवक मंडल के वार्षिकोत्सव पर उजमना उत्सव आयोजित

कोयंबटूर। शहर के आरजी स्ट्रीट के राजस्थानी श्वेतांबर मूर्तिपूजक संघ द्वारा संचालित सुपार्श्वनाथ जैन सेवा मंडल गत 32वर्ष से अनेक सामाजिक, धार्मिक, जीव दया का कार्य करते आ रहा है। इस वर्ष भी मंडल ने आचार्यश्री अभयशेखरसूरीश्वरजी के शिष्य पन्यास श्री आगमशेखर विजयजी व साध्वीश्री निसंगवर्दनाश्रीजी की निश्रा दो दिवसीय उजामना उत्सव का आयोजन किया। सुपार्श्वनाथ मंदिर में दर्शन, ज्ञान और चरित्र का उजमना (सामग्री) देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। मंडल के आशीष जैन, खुशाल जैन, गौरव बोरा आदि टीम ने सहयोग किया

गुरु पूर्णिमा पर हुए अनेक आयोजन

कोयंबटूर//दक्षिण भारत। शहर के उपनगर कनुवाई पंचायत इलाके में स्थित सीरवी समाज के आईमाता मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पतंजलि योग समिति द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह यज्ञ करके आहूति दी गयी। तमिलनाडु पतंजलि के किशोर जैन ने बताया कि कार्यक्रम का संचालन भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष शंकरलाल पटेल ने किया। जयराम सीरवी ने योग क्लास में योग और प्राणायाम के गुर सिखाए। इस अवसर कोषाध्यक्ष नारायणलाल, गंगासिंह राजपूत, सरवन और अन्य योग साधक उपस्थित थे।

सम्मान

चेन्नई के अमृता इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष आर. भूमिनाथन को शिक्षा के क्षेत्र में उनके संस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु आयोजित एक कार्यक्रम में तमिलनाडु के शिक्षा,सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री थिरू राजमोहन ने ईडीयू आइकॉन्स पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.